सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 178, नई दिल्ली, शुक्रवार 05 सितम्बर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अनुशासन एक ऐसा तरीका है जो उसमें कामयाब हो गया वो हर कार्य में जीत सकता है।

03 दिल्ली भाजपा ने पहले नवरात्र से जी.एस.टी. में राहत की घोषणा का स्वागत किया

06 कैसे कल की टेक्नोलॉजीज युद्धस्थान बदल रहे हैं

08 बिजली बिभाग ने 3 मिनट में शिकायत नहीं सुनी तो जुर्माना

नए जीएसटी नियम लागू होने से 22 सितंबर से क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा ?

संजय बाटला

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एवं प्रधानमंत्री मोदी का मध्यम वर्ग के लिए ऐतिहासिक फैसला

जीएसटी रिफॉर्म्स से टैक्स कम किया और बारीकी से देखने पर पता चलता है घर के किसी बड़े ने घरवालों की सेहत और घर की उन्नति के लिए नियम बनाए हो

नए जीएसटी सुधारों के तहत कई वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है, जिससे चीजें सस्ती होंगी:

1. रोजमर्रा की वस्तुएं: हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टॉयलेट सोप, दांतों के ब्रश, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, चीज, पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिश्रित स्नैक्स, बच्चों की फीडिंग बोतल, नैपकिन और क्लिनिकल डायपर (जीएसटी 18% या 12% से घटकर 5%)

2. कृषि से जुड़ी चीजें: ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स, बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, मृदा तैयारी और फसल कटाई की मशीनें (जीएसटी 18% या 12% से घटकर 5%)

3. स्वास्थ्य सेवाएं: व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी खत्म. थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, डायग्नोस्टिक किट्स और रिएजेंट्स, कॉरेक्टिव चश्मे (जीएसटी 5% या 0%)

4. वाहन: पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (कुछ सीमाओं तक), तीन पहिया वाहन, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल, मालवहन वाहन (जीएसटी 28% से घटकर 18%)

5. शिक्षा सामग्री: मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, व्यायाम पुस्तकें, नोटबुक, इरेजर (जीएसटी खत्म)

6. इलेक्ट्रॉनिक्स: एयर कंडीशनर, टीवी (32 इंच से ऊपर के एलईडी और एलसीडी सहित), मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिशवॉशिंग मशीन (जीएसटी 28% से घटकर 18%)

क्या होगा महंगा ?

लग्जरी और हानिकारक वस्तुएं: पान मसाला और तंबाकू जैसे उत्पादों पर फिलहाल 28% जीएसटी और अतिरिक्त सेस लागू रहेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब तक राज्यों का कर्ज चुकता नहीं होता, तब तक यह व्यवस्था रहेगी. बाद में इन पर 40% जीएसटी लगेगा, लेकिन कोई अतिरिक्त ड्यूटी नहीं होगी.

बड़ी कारें: 1200 सीसी से ज्यादा की पेट्रोल कारों और 1500 सीसी से ज्यादा की डीजल कारों पर 40% जीएसटी लगेगा.

नई दरों के लागू होने से और क्या राहत मिलेगी ?

सरकार ने कारोबारियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान कर दिया है. अब तीन दिन में रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जिससे छोटे व्यापारियों और MSME को फायदा होगा.

कमाल कर दिया, जीएसटी रिफॉर्म्स से टैक्स कम किया और बारीकी से देखने पर पता चलता है घर के किसी बड़े ने घरवालों की सेहत और घर की उन्नति के लिए नियम बनाए हो

1. पनीर, दुग्ध, रोटी, पराठा टैक्स फ्री,
2. घी, सूखे मेवे काजू पिस्ता बादाम आदि पर टैक्स कम,
3. कोल्ड ड्रिंक फास्ट फूड पर टैक्स बढ़ाया, यानी सेहतमंद खाओ उल्टा सीधा नहीं जंक फूड नहीं
4. सिगरेट, शराब, पुड़िया तंबाकू पर टैक्स बढ़ा

अर्थात इन सब चीजों से दूर रहे

5. साबुन टूथपेस्ट, तेल शैंपू, शेविंग क्रीम आदि रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स कम

जिससे घर आराम से चल सके

6. रबर पेंसिल मैप्स ग्लोब चार्ट्स कॉपी टैक्स फ्री

जिससे बच्चे खूब पढ़ सकें आगे बढ़ सकें

7. घर का सामान जैसे एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि पर टैक्स कम

जिससे घर पर बोझ ना बढे और आप आराम से जीवन व्यतीत कर सकें

8. घर बनाने की सामग्री जैसे सीमेंट आदि पर टैक्स कम

जिससे हर परिवार अपना घर बना सके

9. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री

अर्थात परिवार की सुरक्षा सर्वोपरि ताकि विपत्ति की स्थिति में आपको परेशान ना होना पड़े

10. जीवन रक्षक दवाएं टैक्स फ्री, बाकी दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर न्यूनतम टैक्स

जिससे आपको दवा सस्ती मिल सके, मेडिकल टेस्ट भी सस्ते

11. ट्रैक्टर, कटाई मशीन, अन्य उपकरण, टैक्सी ऑटो रिक्शा आदि पर टैक्स कम

जिससे आपकी आजीविका का इंतज़ाम हो सके, आप काम करें

12. छोटी कारों पर टैक्स कम लक्जरी कारों पर टैक्स ज्यादा, 350 सीसी से कम की बाइक पर टैक्स कम,

अर्थात्फालतू का दिखावा मत करो, जरूरत की उपयोगी चीज लो।

"टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)"

विचार और धर्म की स्वतंत्रता

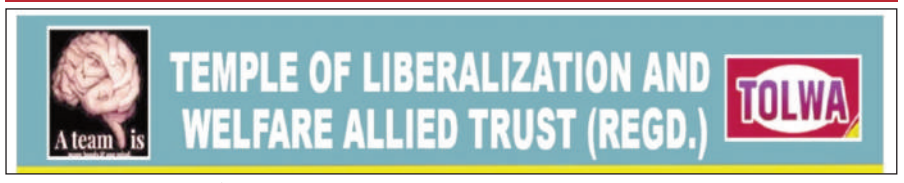

पिंकी कुंडू महासचिव टोलवा ट्रस्ट (पंजीकृत)

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 18 के अनुसार – हर व्यक्ति को विचार, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसमें धर्म या आस्था बदलने का अधिकार और अपने धर्म का पालन, उपदेश, पूजा और आचरण करने की स्वतंत्रता शामिल है – चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या समूह में, सार्वजनिक रूप से हो या निजी रूप से।

कानून बनाम वास्तविकता

कानून में लगभग हर लोकतांत्रिक संविधान इस अधिकार को मान्यता देता है। भारत में अनुच्छेद 25–28 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं (सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन)।

वास्तविकता: जब धार्मिक स्वतंत्रता सामाजिक प्रथाओं, राजनीतिक हस्तक्षेप या राज्य के कानूनों से टकराती है तो विवाद खड़े हो जाते हैं। भारत में अक्सर धर्मांतरण कानून, हिजाब विवाद, मंदिर-मस्जिद विवाद, और अल्पसंख्यकों के अधिकार इस अधिकार को चुनौती देते हैं।

पड़ोसी देशों की स्थिति

पाकिस्तान: संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन अल्पसंख्यक (हिंदू, ईसाई, अहमदी) ज़बरन धर्मांतरण और कठोर ईशनिंदा कानून का सामना करते हैं।

बांग्लादेश: संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, लेकिन अल्पसंख्यकों पर हमले और धार्मिक असहिष्णुता अब भी समस्या है।

नेपाल: हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राज्य बना, लेकिन धर्मांतरण विरोधी कानून तनाव पैदा करते हैं।

चीन: संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, परंतु सरकार का कड़ा नियंत्रण है। उइगर मुसलमान, तिब्बती बौद्ध और भूमिगत ईसाई अत्यधिक दमन झेल रहे हैं।

श्रीलंका और म्यांमार: धार्मिक और जातीय संघर्ष (जैसे रोहिंग्या मुसलमानों का उत्पीड़न) इस अधिकार की नाजुकता दिखाते हैं।

मुख्य विवाद और चुनौतियाँ

1. धर्मांतरण बनाम धर्मांतरण-विरोधी कानून – भारत और नेपाल में सबसे बड़ा विवाद यही है कि धर्म बदलना स्वतंत्रता है या सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा।
2. धार्मिक प्रतीकों का सार्वजनिक प्रयोग – हिजाब, क्रॉस, तिलक, पगड़ी जैसे प्रतीकों पर पाबंदी को लेकर बहस होती रहती है।
3. बहुसंख्यक राजनीति – दक्षिण एशिया के कई देशों में बहुसंख्यक धर्म का दबदबा होता है, जिससे अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस करते हैं।

सच्चाई क्या है? कानून भले ही सभी को पूरी स्वतंत्रता देता है, लेकिन सामाजिक सहिष्णुता, धार्मिक सद्भाव और आपसी सम्मान के बिना यह अधिकार अधूरा रह जाता है। असली स्वतंत्रता तभी संभव है जब हर इंसान को अपने विचार और आस्था के अनुसार जीने का अवसर मिले।

टोलवा ट्रस्ट (पंजीकृत)
tolwaindia@gmail.com

नारी शक्ति महिला कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट और ओमेगा सेईकी मोबिलिटी के सहयोग से दिल्ली में महिलाओं के लिए हुआ बैंगनी ऑटो रिक्शा सेवा का शुभारंभ

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। नारी शक्ति महिला कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट और ओमेगा सेईकी मोबिलिटी के सहयोग से दिल्ली में महिलाओं के लिए बैंगनी ऑटो रिक्शा सेवा का शुभारंभ किया गया है।

यह पहल महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन प्रदान करके सशक्त बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई, यह सेवा महिलाओं को स्वतंत्रता और गरिमा में बढ़ावा देगी। दोनों संगठनों के सहयोगात्मक प्रयास एक समावेशी और सहायक समुदाय बनाने की दिशा में काम कर रहा है!

चालक- परिचालकों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा: योगेश दत्त मिश्रा

परिवहन क्षेत्र की समस्याओं पर श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष से गीता सोनी ने की चर्चा

परिवहन विशेष न्यूज

जांजगीर, छत्तीसगढ़। भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की अखिल भारतीय मंत्री गीता सोनी ने छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा से उनके कार्यालय में सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने परिवहन क्षेत्र में कार्यरत चालक-परिचालकों और उनके परिवारों को हो रही कठिनाइयों एवं समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ट्रक, बस और ई-रिक्शा चालकों की दिक्कतों, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श हुआ। मिश्रा ने महासंघ के कार्यों की सराहना करते हुए सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि चालक-परिचालकों के हितों में मंडल हरसंभव समर्थन देगा। इस अवसर पर गीता सोनी ने कहा कि चालक परिचालकों को हर जिले में संगठित कर उनकी दिक्कतें दूर की जाएंगी।

इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ जिला रायपुर अध्यक्ष बृजेश, जिला जांजगीर सहमंत्री यशपाल चौधरी सहित कई चालक-बंधु उपस्थित थे। गीता सोनी ने कहा कि महासंघ का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र के श्रमिकों को अधिकार दिलाना और उन्हें योजनाओं से जोड़ना है।

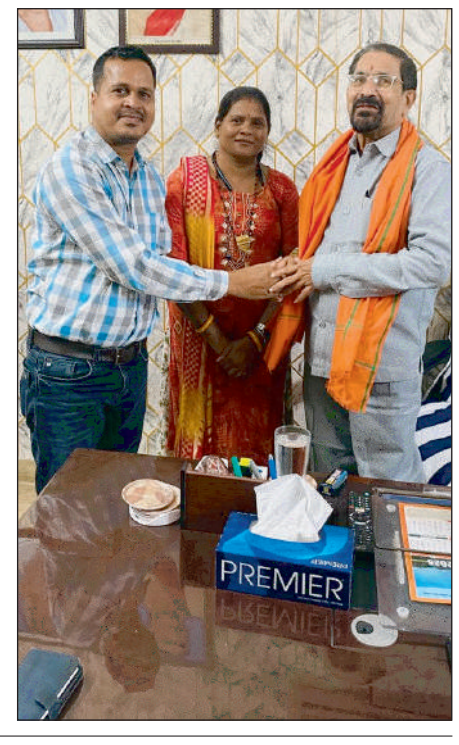

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत के सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए गूगल फार्म पर क्लिक करें और भरकर जमा करे, पिंकी कुंडू, महासचिव टोलवा ट्रस्ट (पंजीकृत अंडर सेक्शन 60), नीति आयोग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, एमएसएमई में पंजीकृत
https://forms.gle/VEThcFgMcknGFc1u9

TEMPLE OF LIBERALIZATION AND SOCIAL WELFARE ALLIED TRUST REGT.

MEMBERSHIP FORM FOR TOLWA TRUST

transportvisheshcontent@gmail.com Switch account

The name, email, and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form

* Indicates required question

How you got aware about TOLWA trust *

- [ ] Social Media
- [ ] News Paper
- [ ] Personal connection
- [ ] Youtube
- [ ] Social Function/ RTO/friends/family

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

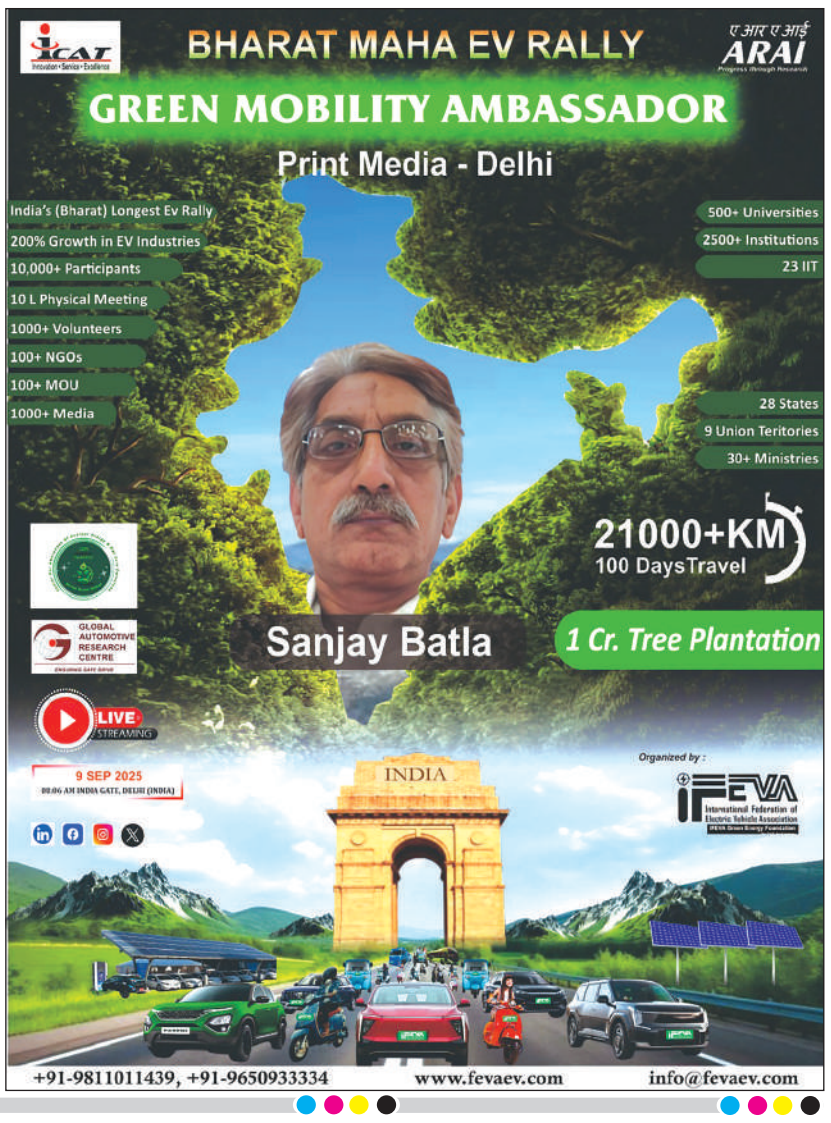

अब समय आ गया है कि अमेरिका का अधीनस्थ सहयोगी बनना बंद करे भारत

(आलेख : प्रकाश करात, अनुवाद : संजय पराते)

यह विडंबना ही है कि भारत की विदेश नीति में लंबे समय से लंबित सुधार करने के लिए मोदी सरकार को मजबूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प को धन्यवाद देना पड़ेगा। वाजपेयी सरकार से लेकर मनमोहन सिंह सरकार तक और फिर मोदी सरकार के दौरान तेज़ गति से लगभग तीन दशकों तक, संयुक्त राज्य अमेरिका का अधीनस्थ सहयोगी बनने की राह पर भारत अग्रसर रहा। यह एक रणनीतिक नीतिगत रुख़ था, जिसने एक स्वतंत्र विदेश नीति के आधार और रणनीतिक स्वायत्तता की गुंजाइश को कमज़ोर कर दिया।

हाल तक, मोदी सरकार गर्व से यह दावा करती रही थी कि उसने अमेरिका के साथ सभी बुनियादी सैन्य समझौते कर लिए हैं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी भू-राजनीतिक रणनीति के साथ तालमेल बिठा लिया है। क्वाड इसी उभरते हुए गठबंधन का एक उदाहरण था। ट्रंप के राष्ट्रपति पद के पहले कार्यकाल में, भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था और ट्रंप द्वारा लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों के अनुरूप काम किया, जिससे हमें भारी नुकसान हुआ। इसके बाद वेनेजुएला से भी तेल खरीदना बंद कर दिया गया।

ट्रंप के दोबारा आगमन को भारत के लिए एक दिव्य अवसर के रूप में देखा गया, जिससे वह ट्रंप और मोदी की व्यक्तिगत मित्रता का लाभ उठाकर अमेरिका के साथ और घनिष्ठता बढ़ा सके। इसी दृष्टिकोण के कारण गाजा में इजरायल द्वारा जारी नरसंहार, जिसे ट्रंप सक्रिय रूप से समर्थन और बढ़ावा दे रहा है, पर शर्मनाक चुप्पी साधी गई। न ही भारत ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी बमबारी की निंदा की, जो एक मित्र देश के विरुद्ध एक आक्रामक कार्रवाई थी, और जिसने परमाणु प्रसार के खतरे को और बढ़ा दिया था।

लेकिन, ट्रंप का उग्र-राष्ट्रवादी रुख और भारत को धमकाने के हथियार के रूप में टैरिफ का इस्तेमाल करने का अतिवाद, मोदी और भाजपा भी पचा पाने में असमर्थ है। न ही वे पाकिस्तान के साथ बराबरी के व्यवहार को बर्दाश्त कर सकते हैं। हकीकत यह है कि जैसे ही भारत और पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश बने, उनके बीच कोई भी सैन्य संघर्ष अमेरिका के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने का रास्ता खोल देता है, क्योंकि दोनों देशों के अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध हैं।

इस साल ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही, राष्ट्रपति बाइडेन के नेतृत्व में मोदी सरकार को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में उसके दायित्वों की याद दिलाने के कई मौके अमेरिका को मिले थे। जुलाई 2024 में जब मोदी रूस गए और राष्ट्रपति पुतिन से मिले, तो बाइडेन प्रशासन ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया था। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका के साथ रिश्ते को भारत हल्के में न लें और

आगे कहा था : मैं जानता हूँ कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पसंद करता है। लेकिन, संघर्ष के समय में रणनीतिक स्वायत्तता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस बात के पर्याप्त संकेत मिले हैं कि भारत अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए रूस पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और साथ ही अमेरिकी हथियारों और उपकरणों की ख़रीद में काफ़ी वृद्धि कर रहा है। यह एक ऐसी माँग है, जो एक के बाद एक आने वाले अमेरिकी प्रशासनों द्वारा निरंतर की जाती रही है और अब ट्रंप के कैबिनेट मंत्रियों द्वारा ज़ोरदार ढंग से उठाई जा रही है।

दक्षिण एशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी दल में शामिल होने के परिणाम, समय के साथ सामने आ रहे हैं। परिणामस्वरूप, भारत की विदेश नीति चरमरा गई है। दक्षिण एशिया में, भारत अपने पड़ोसी देशों से पहले से कहीं अधिक अलग-थलग पड़ गया है। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की निरर्थक कोशिश और जुनूनी पाकिस्तान-केंद्रित नीति, दोनों ही इसके कारण रहे हैं। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण को घुसेड़ने से दुनिया में भारत की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है। अब जब हिंदुत्ववादी जातीय-राष्ट्रवाद, 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (मागा) के नस्लवादी राष्ट्रवाद से टकरा रहा है, तो भारत की अमेरिकापरस्त रणनीतिक और विदेश नीति गतिरोध में हैं। मागा (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन') +मीगा (मेक इंडिया ग्रेट अगेन) मिलकर 'मेगा' नहीं बनाते।

इस संदर्भ में, चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए हाल ही में उठाए गए कदम और शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी की तियानजिन यात्रा तथा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक सकारात्मक घटनाक्रम हैं। चीन विरोधी अंध-द्वेष को दूर करने और दोनों देशों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चीनी निवेश और तकनीक के इस्तेमाल की अपार संभावनाएँ हैं। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में चीनी कंपनियों के निवेश पर लगे प्रतिबंधों को हटाना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, 2023 में सरकार ने इलेक्ट्रिक कार और बैटरी बनाने के लिए, एक भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम में दिग्गज इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी बीवायडी द्वारा एक अरब डॉलर के निवेश को मंजूरी देने से इंकार कर दिया था। इस उद्यम से भारत को नवीनतम तकनीकी जानकारी और उत्पादन क्षमता हासिल करने में मदद मिलती, क्योंकि बीवायडी दुनिया की अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है। ऐसे कई अन्य क्षेत्र हैं, जहाँ चीन के साथ आर्थिक सहयोग से भारतीय उद्योग और बुनियादी ढाँचे के विकास को काफ़ी फ़ायदा होगा।

अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पिछले कुछ समय से पतन की ओर अग्रसर है और बहुध्रुवीयता से उसे लगातार चुनौती मिल रही है। अमेरिकापरस्त नीतियों ने, वास्तव में भारत को बढ़ते बहुध्रुवीय विश्व में खुद को मजबूत करने के अवसरों का लाभ उठाने से रोका है। ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य के रूप में, भारत ने इन मंचों को विकसित और सक्रिय करने में अपना पूरा ज़ोर नहीं लगाया है।

यह संयोग नहीं है कि ट्रंप ने ब्रिक्स के तीन संस्थापक सदस्यों (रूस और चीन के अलावा) ब्राज़ील पर सबसे ज़्यादा टैरिफ़ लगाए हैं -- ब्राज़ील 50 प्रतिशत, दक्षिण अफ्रीका 30 प्रतिशत और भारत 50 प्रतिशत। ये तीनों वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) के प्रमुख देश हैं, जो क्रमशः दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। यह एक ऐसा अवसर है, जो ऐसी नीतियाँ बनाने के लिए नेतृत्व करने का मौका देगा, जो व्यापार और निवेश में ग्लोबल साउथ सहयोग को बढ़ा सकें।

क्या मोदी सरकार में एक नए रास्ते पर साहसपूर्वक आगे बढ़ने का संकल्प और दूरदर्शिता है, जो एक स्वतंत्र विदेश नीति को बहाल करेगा और वास्तव में रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करेगा? या, क्या वह ट्रम्प के मूड में अगले अनुकूल बदलाव का इंतज़ार करेगी और फिर अधीनस्थ सहयोगी बनने की पुरानी राह पर वापस लौट जाएगी?

(सौजन्य : न्यू इंडियन एक्सप्रेस। लेखक माकपा के पूर्व-महासचिव हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध

हर प्रश्न में छिपा है शिक्षक, हर उत्तर में सीख

शिक्षक दिवस, जिसे भारत में हर साल 5 सितंबर को उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जाता है, केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रेरणा और जीवन मूल्यों का एक जीवंत महोत्सव है। यह दिन हमें डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान शिक्षाविद् की याद दिलाता है, जिन्होंने शिक्षा को समाज के उत्थान का सबसे शक्तिशाली माध्यम माना। आज यह दिन न केवल कक्षा की चारदीवारी तक सीमित है, बल्कि यह हमें हर उस व्यक्ति को सम्मानित करने का अवसर देता है जो हमारे जीवन को नए अर्थ, दिशा और संभावनाओं से समृद्ध करता है।

परंपरागत रूप से, शिक्षक वह गुरु था जो ज्ञान का दीप जलाता था, और शिष्य उसकी रोशनी में जीवन पथ पर आगे बढ़ता था। लेकिन आधुनिक युग में शिक्षक की परिभाषा और अधिक व्यापक हो गई है। आज शिक्षक वह नहीं जो केवल किताबी ज्ञान दे, बल्कि वह है जो हमें जीवन की जटिलताओं को समझने, चुनौतियों का सामना करने और मूल्यों को अपनाने की कला सिखाता है। यह माता-पिता हो सकते हैं जो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, दोस्त जो कठिन समय में हौसला देते हैं, या कोई अनजान व्यक्ति जिसकी सलाह हमारे जीवन को नया मोड़ देती है।

शिक्षक दिवस को नए दृष्टिकोण से देखना यही है कि हम इसे केवल एक व्यक्ति या पेशे तक सीमित न करें। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षक समाज का हर वह व्यक्ति है जो हमें कुछ सिखाता है। एक बच्चा अपनी मासूम जिज्ञासा से नया दृष्टिकोण देता है, एक सहकर्मी सहयोग और नेतृत्व की कला सिखाता है, और हमारी असफलताएँ भी हमें धैर्य व दृढ़ता का पाठ पढ़ाती हैं। इस तरह शिक्षक दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि उस निरंतर सीखने की प्रक्रिया का सम्मान है जो हमें हर पल बेहतर बनाती है। यह हमें यह अहसास कराता है कि ज्ञान का कोई एक स्रोत नहीं—यह जीवन के हर अनुभव, हर रिश्ते और हर क्षण में बिखरा हुआ है।

शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान बाँटने तक सीमित नहीं, बल्कि वह एक मूर्तिकार है जो संवेदनशीलता, मानवीयता और नैतिकता को आकार देता है। आज के युग में, जब तकनीकी प्रगति दुनिया को तेजी से बदल रही है, शिक्षक हमें यह सिखाता है कि असली प्रगति मशीनों या व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और सामूहिक कल्याण में निहित है। वह हमें यह समझाता है कि सफलता का अर्थ केवल अपनी जीत नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने का साझा प्रयास है। एक शिक्षक का प्रभाव उसके शब्दों से कहीं अधिक उसके चरित्र, सोच और जीवनशैली में झलकता है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका जीवंत उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान, सादगी और समर्पण से लाखों लोगों को प्रेरित किया।

शिक्षक दिवस को नए अर्थ देने का मतलब है इसे केवल अतीत के सम्मान तक सीमित न रखकर भविष्य की नींव बनाने का उत्सव बनाना। शिक्षक का दायित्व महज पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन की अनिश्चितताओं और चुनौतियों के लिए तैयार करना है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में, जहाँ परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है, शिक्षक वह आधार प्रदान करता है जो हमें हर बदलाव के साथ सामंजस्य बैठाने की शक्ति देता है। वह हमें सिखाता है कि असफलताएँ रुकावट नहीं, बल्कि नई शुरुआत का द्वार हैं। वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर कठिनाई में अवसर छिपा है और हर सवाल में एक नया जवाब।

शिक्षक दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है, जो हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों, व्यवहार और जीवनशैली से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनें। चाहे वह कक्षा में बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक हो, नैतिकता का पाठ सिखाने वाले माता-पिता हों, या समाज में बदलाव लाने वाला कार्यकर्ता हो—हर व्यक्ति अपने स्तर पर शिक्षक की भूमिका निभाता है। इस दिन को मनाने का अर्थ है उन सभी स्रोतों को सम्मान देना जिन्होंने हमें गढ़ा, और स्वयं को इस कर्तव्य के लिए प्रेरित करना कि हम भी दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएँ।

शिक्षक दिवस को व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो यह केवल एक दिन या व्यक्ति का उत्सव नहीं, बल्कि वह अनंत श्रृंखला है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। हर पीढ़ी अपने ज्ञान और अनुभवों को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करती है, जो उसे नए संदर्भों में समृद्ध करती है। यह एक जीवंत संवाद है, जो समय के साथ विकसित होता रहता है। शिक्षक दिवस हमें सिखाता है कि शिक्षा कभी स्थिर नहीं; यह एक गतिशील प्रक्रिया है, जो हर पल हमें कुछ नया सिखाती है और जीवन को समृद्ध बनाती है।

शिक्षक दिवस को नए अर्थ देना यही है कि इसे औपचारिकता से परे ले जाकर जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा केवल कक्षा की चारदीवारी तक सीमित नहीं, बल्कि यह हर अनुभव, हर रिश्ते और हर क्षण में बिखरी हुई है। हम सभी एक साथ शिक्षक और शिष्य हैं, और यह सिलसिला अनवरत चलता रहता है। शिक्षक दिवस का असली उत्सव तब है जब हम अपनी जिज्ञासा को जीवित रखते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, और हर अनुभव से सीख लेते हैं। यह दिन केवल सम्मान का प्रतीक नहीं, बल्कि उस अनंत यात्रा का उत्सव है जिसमें हम सभी सहयात्री हैं—कभी शिक्षक, कभी शिष्य, और हमेशा एक सीखने वाले। यही शिक्षक दिवस का सच्चा अर्थ है, जो इसे आज के युग में सही मायनों में जीवंत और प्रासंगिक बनाता है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

चूहे काटते रहे, तंत्र सोता रहा — दो नन्ही जानें गईं

मध्य प्रदेश के इंदौर, जो स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है, वहां के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चूहों का आतंक और दो नवजातों की दिल दहलाने वाली मृत्यु ने स्वास्थ्य व्यवस्था की भयावह विफलता को उजागर कर दिया है। यह अस्पताल, जो लाखों मरीजों की उम्मीदों का आधार है, वहां नवजात गहन चिकित्सा इकाई जैसे अति संवेदनशील वार्ड में चूहों ने कहर ढाया। २४ अगस्त को एक 10 दिन की बच्ची को ३1 अगस्त को चूहों ने काट लिया, और २ सितंबर को उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। इसके बाद, ३ सितंबर को एक और नवजात की मृत्यु ने पूरे तंत्र को हिलाकर रख दिया। अस्पताल प्रशासन इसे जन्मजात हृदय रोग और संक्रमण का परिणाम बताता है, मगर बेख़ौफ विचरण करते चूहे, एक बच्चे के सिर और कंधे पर काटने के निशान, और दूसरे की उंगलियों पर घाव सच्चाई को चीख-चीखकर उजागर करते हैं। यह लापरवाही का वह घृणित चेहरा है, जहां मासूमों की जान तक को खतरा है।

यह त्रासदी केवल एक अस्पताल की कहानी नहीं, बल्कि पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का द्योतक है। स्वच्छता का अभाव, रखरखाव में घोर लापरवाही, और निगरानी की कमी ने चूहों को वार्डों में खुला निमंत्रण दिया। वर्षों से पेस्ट कंट्रोल के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। हाल की बारिश ने जलभराव से स्थिति को और विकराल बना दिया, जिससे चूहे पाइपों के रास्ते नवजात इकाई तक पहुंच गए। स्टाफ को इस संकट की जानकारी थी, फिर भी उनकी उदासीनता ने हालात को और बदतर किया। परिजनों द्वारा लाया गया भोजन चूहों को आकर्षित करता रहा, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं खोजा गया। १२ हजार से अधिक चूहों को मारने का दावा महज एक खोखला वादा साबित हुआ, क्योंकि खतरा अब भी बरकरार है। इंदौर, जो स्वच्छता में देश का गौरव है, वहां अस्पतालों में चूहों का राज शर्मिंदगी का सबब है। यह विडंबना दर्शाती है कि स्वच्छता अभियान केवल सतही चमक तक सीमित है, जबकि जमीनी हकीकत रोंगटे खड़े करने वाली है।

राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर और शोचनीय स्थिति कोई छिपा रहस्य नहीं। चिकित्सकों की घोर कमी, जीर्ण-शीर्ण उपकरण, और कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या ने अस्पतालों को निष्क्रियता की गहरी खाई में धकेल दिया है। नवजात गहन चिकित्सा इकाई, जहां अति सतर्कता और सुरक्षा अनिवार्य है, वहां बुनियादी संरक्षण का अभाव है। ऐसी हृदयविदारक घटनाएं व्यवस्थागत सड़ांध की क्रूर गवाही देती हैं, जहां लापरवाही बार-बार मासूमों की जिंदगी छीन रही है। विपक्ष ने इसे सरकार की घनघोर विफलता करार देते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। माता-पिताओं के दिलों में भय का साया पसरा है—यदि अस्पतालों में नवजात शिशु असुरक्षित हैं, तो निर्धन परिवार अपनी उम्मीदें कहां टिकाएं? स्वास्थ्य असमानता अपने चरम पर है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां सुविधाएं दयनीयता की हदें पार करती हैं। यह त्रासदी समाज के सबसे कमजोर तबके की दुर्दशा को नंगा करती है, जो निजी अस्पतालों के खर्च से वंचित हैं।

प्रशासन ने कुछ कदम उठाए, मगर ये नाकाफी और विलंबित हैं। दो नर्सिंग अधिकारियों का निलंबन, नर्सिंग अधीक्षक का स्थानांतरण, और सफाई-पेस्ट कंट्रोल कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना महज सतही दिखावा है। साप्ताहिक पेस्ट कंट्रोल, खिड़कियों पर लोहे की जालियां, २४ घंटे निगरानी, और बाहर के भोजन पर प्रतिबंध जैसे निर्देश अब जारी हुए हैं। एक उच्चस्तरीय समिति सात दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, और राज्य मानवाधिकार आयोग ने सवाल उठाया है कि चूहे वार्ड तक कैसे पहुंचे। किंतु क्या ये उपाय भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोक पाएंगे? जवाबदेही सुनिश्चित किए बिना सुधार अधूरे हैं। कर्मचारियों की नियमित ट्रेनिंग, कठोर निरीक्षण, और बजट का पारदर्शी आवंटन अनिवार्य है। कंपनी को चेतावनी दी गई, पर सजा की प्रभावशीलता संदिग्ध है। यह प्रश्न अब भी अनुत्तरित लटका हुआ है, जो व्यवस्था की नाकामी को और गहरा करता है।

यह त्रासदी समाज की आत्मा को झकझोर देने वाली है। अस्पताल, जो जीवन की रक्षा का पवित्र मंदिर होना चाहिए, मृत्यु के भयावह अड्डों में तब्दील हो रहे हैं। माता-पिताओं का विश्वास चूर-चूर हो चुका है, और निर्धन परिवारों की अंतिम उम्मीदें राख में मिल रही हैं। सरकार को तत्काल सभी सरकारी अस्पतालों का गहन ऑडिट कराना होगा। पेस्ट कंट्रोल को अनिवार्य बनाना, कर्मचारियों की कठोर जवाबदेही सुनिश्चित करना, और नवजात स्वास्थ्य कार्यक्रमों को अटल आधार देना समय की पुकार है। स्वास्थ्य बजट में व्यापक वृद्धि कर जर्जर बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना अनिवार्य है। पारदर्शिता और कठिन निगरानी के अभाव में कोई सुधार संभव नहीं। यह घटना महज एक हादसा नहीं, बल्कि व्यवस्था की गहरी खाइयों का क्रूर दर्पण है। यदि चूहों जैसे छोटे खतरे को अनदेखा किया गया, तो यह और भी भयंकर त्रासदियों को निमंत्रण देगा। यह समय केवल शोक में डूबने का नहीं, बल्कि निर्णायक और ठोस कदम उठाने का है। सरकार को स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, विशेषकर उस राज्य में जहां जनसंख्या का दबाव असहनीय है। नवजातों की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल प्रशासन का कर्तव्य नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यह त्रासदी परिवर्तन का एक सशक्त उत्प्रेरक बने, ताकि कोई और मासूम चूहों की क्रूरता का शिकार न हो। अस्पतालों को मृत्यु का अखाड़ा नहीं, बल्कि जीवन का संरक्षक बनाना होगा। जनता का विश्वास तभी लौटेगा, जब स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही, और मानवता का संचार होगा। यह घटना भूलने की नहीं, बल्कि गहरे सबक लेने की है, ताकि भविष्य में कोई और नन्हा जीवन इस घृणित लापरवाही का बलिदान न बने। मध्य प्रदेश को इस कलंक को मिटाने के लिए अब त्वरित, कठोर, और प्रभावी कदम उठाने होंगे।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

"नेताओं को सब, कर्मचारियों को कब?"

"जनता और कर्मचारियों की एक पेंशन ही जीवनभर का सहारा, पर नेताओं के लिए अनेक पेंशन और असीमित सुविधाएँ – यही है लोकतंत्र की असली विसंगति।"

-डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जनता सर्वोपरि मानी जाती है। संविधान में समानता, न्याय और समान अवसर की बात कही गई है। लेकिन जब बात नेताओं और आम जनता की सुविधाओं की आती है तो तस्वीर बिल्कुल उलट दिखती है। जिस देश में करोड़ों लोग बुढ़ापे की लाठी के तौर पर केवल एक मामूली सी पेंशन पर निर्भर हैं, वहां नेताओं के लिए पेंशन और सुविधाओं की भरमार है। सवाल उठता है कि आखिर लोकतंत्र में यह असमानता क्यों?

बार-बार पेंशन, सुविधा पर सुविधा, यात्रा भत्ता, सुरक्षा, मेडिकल, स्टाफ़ और आवास—all free. दूसरी ओर, कर्मचारी चाहे 35–40 साल तक ईमानदारी से काम करे, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का इंतज़ार करता है और अक्सर अदालतों व आंदोलन का सहारा लेना पड़ता है।

मान लीजिए एक आम कर्मचारी 35 साल नौकरी करता है। सेवा पूरी होने के बाद उसे मुश्किल से इतनी पेंशन मिलती है कि घर का राशन-पानी चल सके। महँगाई, दवाइयों और बच्चों की ज़िम्मेदारी के बीच वह पेंशन अपर्याप्त साबित होती है। अब ज़रा नेताओं का हाल देखिए—उपराष्ट्रपति की पेंशन ₹2.25 लाख मासिक, सांसद की पेंशन ₹27,500 मासिक और विधायक की पेंशन ₹42,000 मासिक। यानी एक ही व्यक्ति अगर अलग-अलग पदों पर रहा है तो उसे तीन-तीन पेंशन मिलेगी। और यह यहीं नहीं रुकती। उसे जीवनभर सरकारी गाड़ी, स्टाफ़, सुरक्षा, हवाई और रेल यात्रा पर छूट, मेडिकल का पूरा ख़र्च और न जाने क्या-क्या मुफ्त मिलता रहता है।

कर्मचारी वर्ग को देखिए—महँगाई राहत का हिसाब सालों तक लटकता है, पेंशन रिवीजन की माँग दशकों तक पूरी नहीं होती। दो-दो वेतन आयोग आ चुके हैं, फिर भी पेंशन सुधार की फ़ाइल धूल खा रही है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विधायक या सांसद एक दिन के लिए भी सदन में बैठ जाए तो उसकी पेंशन पक्की। वहीं एक सरकारी कर्मचारी अगर एक दिन कम सेवा पूरी करता है तो उसकी पेंशन ही कट सकती है। संविधान की यही विसंगति नेताओं को "सुपर क्लास" बना देती है। जनता टैक्स चुकाती है, सरकारी खज़ाना भरती है, और उसी पैसे से नेताओं की आलीशान रिटायरमेंट ज़िंदगी चलती है।

अगर हम नैतिकता की बात करें तो किसी भी संवैधानिक पद या जनप्रतिनिधि को एक ही पेंशन मिलनी चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व सांसद—सबको एक पेंशन। लेकिन आज हालत यह है कि वही नेता कई पेंशन ले रहा है और आम जनता एक पेंशन के लिए तरस रही है। नैतिक दृष्टि से देखें तो जब आम आदमी को एक ही पेंशन पर जीवन बिताना पड़ता है तो नेताओं को क्यों विशेषाधिकार मिले? यह सीधी-सीधी असमानता है और लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है।

वास्तविकता यह है कि यह मुद्दा केवल पेंशन का नहीं, बल्कि राजनीति की लूट का है। नेता जानते हैं कि जनता स्मृति-विलोप की शिकार है। जनता को आज गुस्सा आता है लेकिन कल भूल जाती है। इसी भूलने की आदत पर भरोसा करके नेता कभी अपने भत्ते बढ़ाते हैं, कभी सुविधाएँ जोड़ते हैं और कभी पेंशन के नए नियम बना लेते हैं। दूसरी तरफ़, कर्मचारियों और पेंशनरों को हर सुविधा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन और याचिका—फिर भी सुनवाई नहीं होती।

लोकतंत्र में नेता जनता के सेवक माने जाते हैं। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि नेता सेवक कम और शासक ज़्यादा बन गए हैं। उन्हें अपने लिए हर सुविधा चाहिए, चाहे जनता पर कितना भी बोझ क्यों न पड़े। जनता टैक्स देती है इस उम्मीद में कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और आधारभूत ढाँचे में सुधार होगा। लेकिन टैक्स का बड़ा हिस्सा नेताओं की पेंशन और सुविधाओं पर खर्च हो रहा है।

इस स्थिति को बदलने के लिए ज़रूरी है कि एक पद, एक पेंशन का नियम लागू हो। जिस तरह सैनिकों और कर्मचारियों पर यह नियम लागू है, उसी तरह नेताओं पर भी होना चाहिए। किसी भी पदाधिकारी की पेंशन एक निश्चित सीमा से अधिक न हो। रिटायरमेंट के बाद हवाई यात्रा, मेडिकल, गाड़ी और स्टाफ़ जैसी मुफ्त सुविधाएँ बंद की जाएँ। जनप्रतिनिधियों की पेंशन की समीक्षा संसद और विधानसभाओं के बाहर एक स्वतंत्र आयोग से हो। सबसे अहम बात यह कि जनता को जागरूक किया जाए ताकि यह मुद्दा हर चुनाव में उठे और राजनीतिक दलों को इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करना पड़े।

भारत में पेंशन का यह दोहरा मानदंड लोकतंत्र की आत्मा को आहत करता है। एक ओर जनता और कर्मचारी वर्ग अपनी बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए संघर्षरत हैं, वहीं नेता टैक्स के पैसों पर ऐश कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि देश में "एक पद, एक पेंशन" का नियम बने। नेता भी वही पेंशन लें जो एक आम नागरिक लेता है। लोकतंत्र तभी मज़बूत होगा जब जनता और नेताओं के बीच बराबरी का भाव होगा, न कि विशेषाधिकार का फर्क।

आज देश के युवाओं, कर्मचारियों और पेंशनरों को एक स्वर में यह सवाल पूछना चाहिए—"जब हमें एक पेंशन काफ़ी है तो नेताओं को कई पेंशन क्यों?"

भारत में नेताओं को अनेक पेंशन और असीमित सुविधाएँ प्राप्त हैं, चाहे वे एक दिन ही सदन में बैठे हों। वहीं करोड़ों कर्मचारी दशकों तक सेवा करने के बाद भी पेंशन के लिए तरसते हैं। दो-दो वेतन आयोग आने के बावजूद वर्षों से पेंशन संशोधन लंबित है। आम नागरिक एक पेंशन पर जीवन यापन करता है, जबकि नेता तीन-तीन पेंशन और मुफ्त सुविधाओं का उपभोग करते हैं। लोकतंत्र की आत्मा यही कहती है कि सबके लिए नियम समान हों। अब समय आ गया है कि "एक पद, एक पेंशन" का सिद्धांत नेताओं पर भी लागू हो।

कुदरत का संदेश

कुदरत का रूठना भी ज़रूरी था,
इंसान का घमंड टूटना भी ज़रूरी था।
हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा,
उस वहम का छूटना भी ज़रूरी था।

पेड़ कटे, नदियाँ रोईं, पर्वत भी कांपे,
धरती माँ की कराहें कौन था आँके।
लोभ में अंधा हुआ इंसान इतना,
उसको आईना दिखाना भी ज़रूरी था।

आंधियाँ, तूफ़ान, बारिश का प्रहार,
दे गए चेतावनी – बचो, संभलो बार-बार।
जीवन का असली सच बताना भी ज़रूरी था,
नश्वरता का एहसास कराना भी ज़रूरी था।

कुदरत ने सिखाया – मत बनो अभिमानी,
बूँद-सी है तेरी ज़िंदगी की कहानी।
विनम्र रहो, और धरती को बचाओ,
प्रकृति का ज्ञान जगाना भी ज़रूरी था।

--- डॉ सत्यवान सौरभ

अगर आपको दिन में कई बार चक्कर आता है तो हो सकता है कि आपको वर्टिगो नामक बीमारी हो

सिर दर्द, चक्कर, नॉजिया- ये वर्टिगो के लक्षण हैं। वर्टिगो टिन का शब्द है, जिसका अर्थ है चक्कर आना। दरअसल इसमें यह एहसास होता है कि सब कुछ घूम रहा है। इसमें कभी-कभी चक्कर के साथ उल्टी जैसा भी महसूस होता है। अगर आपको लगातार कई महीनों से चक्कर आ रहे हैं तो उसे नजरअंदाज न करें।

अगर आपको भी ज्यादा चक्कर आते हैं तो ज्यादा चाय-कॉफी और तले-भुने खाने से परहेज करना चाहिए।

अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम से चक्कर आने की समस्या में आराम मिलता है।

कई घरेलू चीजे हैं जिससे इसमें आराम मिलता है, आइये जानते हैं उन घरेलू चीजों के बारे में..

नारियल पानी

रोज सुबह-शाम नारियल पानी पीने से चक्कर (वर्टिगो) नहीं आते।

खरबूजे के बीज

खरबूजे के बीजों को गाय के घी में भूनकर सुबह शाम खाने से चक्कर आने की समस्या में आराम मिलता है।

धनिया और आंवले का रस

आधा कप धनिया के रस में 2 चम्मच आंवले का रस मिलाकर पीने से चक्कर आने की समस्या ठीक हो जाती है।

नींबू का रस

एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीने से चक्कर नहीं आते।

अदरक

चक्कर आने पर अदरक की चाय या अदरक चूसने से फायदा होता है। उल्टी में भी राहत मिलती है

इलायची

छोटी इलायची के दानों को चबाने से चक्कर आने और उल्टी जैसी प्रॉब्लम दूर हो जाती है।

ठंडा पानी

चक्कर आने और सिर घूमने पर 2-3 गिलास ठंडा पानी पीने से काफी फायदा होता है।

चक्कर आने पर तुलसी के रस में चीनी मिलाकर सेवन करने से या तुलसी के पत्तों में शहद मिलाकर चाटने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं।

चक्कर आने पर धनिया पाउडर दस ग्राम और आंवले का पाउडर दस ग्राम लेकर एक गिलास पानी में भिगो कर रख दें। सुबह अच्छी तरह मिलाकर पी लें। इससे चक्कर आने बंद हो जाते हैं।

सिर चकराने पर आधा गिलास पानी में दो लौंग डालकर उसे उबाल लें और फिर उस पानी को पी लें। इस पानी को पीने से फायदा मिलता है।

10 ग्राम आंवला, 3 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम बताशे को पीस लें। 15 दिनों तक रोजाना इसका सेवन करें चक्कर आने बंद हो जाएंगे।

सत्य वह दृष्टि है जहां हम संसार की किसी बात से संबंधित नहीं होते। जैसे ही हम किसी वस्तुस्थिति का सहारा लेते हैं हम सत्य से चूक जाते हो।

यदि हम सत्य को प्रकाश कहते हैं तो भी अंधकार का वजूद भी साथ में रहेगा। यदि हम सत्य को ज्ञान कहते हैं तो भी अज्ञान साथ रहेगा। यदि हम कुछ भी कहते हैं तो विपरीतार्थी कुछ कुछ तो बचा ही रहेगा। जहां भी हमने सत्य को किसी के साथ जोड़ा या घटाया, सत्य आधा/ अधूरा/ अपूर्ण/अशुद्ध हो जाएगा। ध्यान रहे कि अभी हमारी दृष्टि असमर्थ है सत्य को अपने में समेटने में। सत्य को संसार की किसी भी वस्तु से संबंधित/रिलेट नहीं किया जा सकता। 'सत्य' वह दृष्टि है जो हमें पूर्णता का बोध कराती है और 'मृत्यु' संसार के अज्ञान के पर्दे को गिराकर, हमें जीवन में प्रवेश करा देती है। होश रहे कि इस संसार की कोई सीमा-रेखा नहीं है इसलिए तुलनात्मक किसी वस्तु से उसका उल्लेख/रिलेशन नहीं बताया जा सकता। शुद्धतम परिपूर्ण स्वभाव में खिला हुआ समग्र जीवन हमें बता देता है कि यह समस्त ब्रह्माण्ड टुकड़ों में बंटा हुआ नहीं है, यह उस एक से ही बना है, और उस एक में ही विसर्जित है, इसीलिए हमारे मनीषियों ने इसे अद्वैत कहा है। एक या दो कहने का कोई औचित्य ही नहीं रहा, अद्वैत बहुत वैज्ञानिक शब्द है।

दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कॉमर्स
DELHI COLLEGE OF ARTS & COMMERCE
दिल्ली विश्वविद्यालय
(University of Delhi)
नेताजी नगर, नई दिल्ली–110023
Netaji Nagar, New Delhi - 110023

Advt. No. DCAC/Advt./NTS/2025/321 Dated: 24.06.2025

Online Application forms are invited for the following Non-Teaching post(s) on permanent basis:

Details of posts to be filled

S. no.	Name of the Post	Pay Level	Total No. of posts	UR	SC	ST	OBC	EWS	PwBD	Age Limit
1	Director of Physical Education	10	01	01	--	–	–	–	--	As per University of Delhi Rules
2	Senior Technical Assistant (Computer)	06	01	--	--	--	--	--	01 (HI)	35 years
3	Professional Assistant	06	02	02	--	--	–	--	--	35 years
4	Semi Professional Assistant	05	01	--	01	--	--	--	--	32 years
5	Library Attendant	01	01	01	--	–	–	–	–	32 years

*** The posts will be filled up after due approval of UGC and the University of Delhi.**

The last date of receipt of application is 21.09.2025 or within two weeks from the date of publication of the advertisement in the Employment News, whichever is later. For details, please visit College website https://www.dcac.du.ac.in. The link for submission of application is https://dunt.uod.ac.in.

Any addendum/dedendum/corrigendum shall be posted on the College website only.

Important Note: The details regarding qualifications, experience, screening guidelines and indicative performs etc. are available on the College website: https://www.dcac.du.ac.in under the menu-item Recruitment along with this advertisement. Age relaxation will be given as per the rules of University of Delhi and UGC. The applicants are required to read these details before filling up the form.

PRINCIPAL

FREE HEALTH CHECK-UP CAMP
Organised by :
St. John Ambulance Brigade Delhi
on 07th Sep. 2025 (Sunday) 09:00am to 02:00pm

ST. JOHN AMBULANCE (INDIA) BRIGADE WING, DELHI
Courtesy :-
Gurudwara Singh Sabha Giri Nagar &
Guru Amardas Sewa Trust
Govind Puri, Kalkaji, New Delhi
Contact No : Guru Amardas Sewa Trust
9350791313, 9268581313

स्टॉल प्रस्ताव :
सिंगल साइड ओपन स्टोल : 2000
कॉर्नर साइड स्टोल : 3500
तीन साइड ओपन स्टोल : 4500
सिर्फ एक टेबल : 1000
सिर्फ दो टेबल : 1250

कार्यक्रम विवरण :
रक्षा गरबा–डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव
स्थान : डीडीए ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड के सामने, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बगल में, PNB बैंक के पीछे, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

तारीखें : 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025
* दुकान का आकार : 10 फीट x 10 फीट
* शामिल सुविधाएँ :
* 2 कुर्सियाँ * 2 टेबल
*लाइट व चार्जिंग प्वाइंट

भुगतान की शर्तें :
* अग्रिम भुगतान आवश्यक
* बुकिंग के समय 50% भुगतान
* कब्जे के समय 50% भुगतान
संपर्क : इंदु राजपूत
मोबाइल : 9210210071

रक्षा द सेवियर की ओर से प्रस्तुत
गरबा महोत्सव में विशेष अपील
हमारी रक्षा द सेवियर की ओर से
रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव में आने वाले सभी लोगों से विनम्र निवेदन है—
इस नवरात्रि एक सेवा ड्राइव चलाई जा रही है

आप अपने घर से लाएँ और दान करें :
- पुराने कपड़े
- पुराने कंबल
- पुराने जूते-चप्पल
- बच्चों के लिए बैग
- किताबें

आपका छोटा-सा योगदान किसी ज़रूरतमंद के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है

स्थान :
रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव
रामलीला मैदान के सामने, आरटीओ ऑथोरिटी के पास
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

विशेष सूचना
नवरात्रि में मातारानी की खंडित मूर्तियाँ, टूटे हुए फ़ोटो, पुरानी चुनरियाँ और नवरात्रि में बोए गए जवारों का विसर्जन
- दशहरे के दूसरे दिन
- दिनांक : 3 अक्टूबर की सुबह
- स्थान : रक्षा नवरात्रि गरबा एवं दुर्गा पूजा ग्राउंड

स्थान विवरण :
रामलीला मैदान के सामने,
आरटीओ ऑथोरिटी के पास,
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली
संपर्क सूत्र :
इंदु राजपूत – 9210210071
सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस पावन विसर्जन में सहभागी बनें।

राहत और चुनौती साथ-साथ: जीएसटी में क्रांतिकारी बदलाव

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के क्षेत्र में 3 सितंबर को एक युगांतरकारी और परिवर्तनकारी घोषणा ने भारत की कर व्यवस्था को अभूतपूर्व दिशा दी। जीएसटी परिषद की सभा में सर्वसम्मति से एक सरल, दो-स्तरीय कर ढांचे को स्वीकृति मिली, जिसमें 12% और 28% के पुराने स्तरों को समाप्त कर 5% और 18% की नवीन, सुगम दरें लागू की गई हैं। यह ऐतिहासिक बदलाव 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। इस निर्णय से दैनिक उपयोग की वस्तुएँ, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से जुड़े उत्पाद व सेवाएँ और अधिक सस्ती हो जाएँगी, हालाँकि सरकार को 93,000 करोड़ रुपये के राजस्व हानि का अनुमान है। यह कदम न केवल उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए राहतकारी है, बल्कि भारत की आर्थिक नीतियों और संघीय संरचना को एक सशक्त, प्रगतिशील और समावेशी भविष्य की ओर ले जाएगा।

2017 में लागू जीएसटी का लक्ष्य जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल और एकीकृत करना था, लेकिन चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) और विशेष दरों (0%, 0.25%, 3%) ने इसे जटिल बनाए रखा। व्यवसायों को अनुपालन में चुनौतियों और उपभोक्ताओं को उच्च करों का सामना करना पड़ा। नई दो-स्लैब व्यवस्था इस दिशा में एक साहसिक और स्वागतयोग्य सुधार है। हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन, बटर, घी, चीज़, पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, बर्तन, बच्चों की दूध की बोतल, नैपकिन, डायपर और सिलाई मशीनों पर जीएसटी अब केवल 5% होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी 18% से घटाकर शून्य कर दिया गया, जबकि थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट और ग्लूकोमीटर पर 5% कर लागू होगा। शिक्षा क्षेत्र में मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर और नोटबुक जैसी वस्तुएं कर-मुक्त होंगी। कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर टायर, बायो कीटनाशक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। ये सुधार निम्न और मध्यम वर्ग के लिए विशेष रूप से लाभकारी होंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और जीवनयापन आसान होगा।

भारत की नई जीएसटी व्यवस्था उपभोक्ताओं, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगी। इस सुधार के फायदे स्पष्ट और दूरगामी हैं। पहला, रोजमर्रा की जरूरतों जैसे हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, बटर, घी और चीज़ पर कर घटने से निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों का घरेलू बजट हल्का होगा। इससे खाद्य मुद्रास्फीति पर भी अंकुश लगेगा, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए राहतकारी है। दूसरा, स्वास्थ्य और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी शून्य होने से बीमा योजनाएँ सस्ती होंगी, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण भारत में अधिक लोग स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ उठा सकेंगे। यह भारत जैसे देश में, जहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ महँगी हैं, एक क्रांतिकारी कदम है। तीसरा, शिक्षा क्षेत्र में मैप, चार्ट, पेंसिल और नोटबुक जैसी स्कूली सामग्री पर जीएसटी शून्य होने से शिक्षा सस्ती और समावेशी बनेगी, जिससे गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर अवसर मिलेंगे। चौथा, कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर टायर, बायो कीटनाशक और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर कर 12% से घटाकर 5% करने से किसानों की लागत कम होगी, जिससे टिकाऊ खेती और जल-संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत जैसे कृषि-प्रधान देश के लिए एक दूरदर्शी कदम है। दो स्लैब वाली सरल जीएसटी व्यवस्था से व्यवसायों के लिए अनुपालन आसान होगा, कर चोरी कम होगी और 'एक देश, एक कर' का सपना साकार होगा।

हालांकि, इस सुधार की चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी चिंता 93,000 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे की है, जो सरकार के वित्तीय घाटे को बढ़ा सकता है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को प्रत्यक्ष करों या गैर-कर राजस्व जैसे वैकल्पिक स्रोत तलाशने होंगे, वरना बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश प्रभावित हो सकता है। दूसरा, राज्यों को होने वाली राजस्व हानि एक गंभीर मुद्दा है। छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर राज्य, जो जीएसटी आय पर निर्भर हैं, विकास कार्यों जैसे सड़क, स्कूल और अस्पतालों के लिए संसाधनों की कमी का सामना कर सकते हैं। तीसरा, प्रस्तावित 40% स्लैब, जिससे 45,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय की उम्मीद है, अस्पष्टता का कारण है। यदि यह विलासिता की वस्तुओं (जैसे लग्जरी कार या शराब) पर लागू होता है, तो यह स्वीकार्य होगा, लेकिन आवश्यक वस्तुओं पर लागू होने से मध्यम वर्ग पर बोझ बढ़ सकता है। चौथा, कुछ वस्तुएँ जो पहले 12% या 28% स्लैब में थीं, अब 18% स्लैब में आ सकती हैं, जिससे उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं और महंगाई को बढ़ावा मिल सकता है। अंत में, नई दरों का कार्यान्वयन छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि उन्हें अपनी लेखा प्रणाली, मूल्य निर्धारण और आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव के लिए समय और लागत निवेश करनी होगी।

भारत की नई जीएसटी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करना और इसके नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। राजस्व घाटे की चुनौती से निपटने के लिए ठोस और नवोन्मेषी उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला, शराब, तंबाकू और लग्जरी कार जैसी विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40% स्लैब लागू कर राजस्व को बढ़ाया जा सकता है, जिससे आवश्यक वस्तुओं पर कर बोझ कम रहे। दूसरा, आयकर और कॉर्पोरेट कर में सुधार के जरिए अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सकता है, जो कर आधार को और व्यापक बनाएगा। तीसरा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, जैसे ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं, पर कर वसूली को और सशक्त कर राजस्व की कमी को पूरा किया जा सकता है। चौथा, राज्यों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी और त्वरित मुआवजा योजना लागू करनी होगी। साथ ही, छोटे और मध्यम उद्यमों को नई व्यवस्था के अनुपालन में सहायता के लिए सरकार को जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए, ताकि उनकी परिवर्तन प्रक्रिया सुगम हो।

यह जीएसटी सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को उपभोक्ता-केंद्रित, सरल और समावेशी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह न केवल रोजमर्रा की वस्तुओं को सस्ता कर उपभोक्ताओं को राहत देगा, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा को अधिक सुलभ बनाएगा, और कृषि क्षेत्र को सशक्त करेगा। कोविड-19 के बाद आर्थिक पुनरुत्थान के दौर में यह सुधार उपभोक्ता विश्वास और खपत को बढ़ाने में उत्प्रेरक साबित होगा। हालांकि, 93,000 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे, राज्यों की वित्तीय चिंताओं और 40% स्लैब की अस्पष्टता जैसे मुद्दों का त्वरित और प्रभावी समाधान आवश्यक है। यदि सरकार इन चुनौतियों को रणनीतिक ढंग से संबोधित करती है, तो यह सुधार भारत को एक अधिक लचीली, समावेशी और गतिशील अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा। यह न केवल कर प्रणाली को सरल बनाएगा, बल्कि भारत के आर्थिक विकास को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने "विकास भी, विरासत भी" थीम पर एनडीएमसी की शैक्षिक पहल का शुभारंभ किया

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर एनडीएमसी की नई शैक्षिक पहल - ₹विकास भी, विरासत भी₹ का शुभारंभ किया, जिससे एनडीएमसी स्कूलों के 28,000 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे और इस अवसर पर एनडीएमसी के 15 शिक्षकों को भी सम्मानित किया।

इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री - प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, सांसद (नई दिल्ली) - बांसुरी स्वराज, अध्यक्ष - एनडीएमसी, केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष- कुलजीत सिंह चहल, परिषद सदस्य- अनिल वाल्मीकि, दिनेश प्रताप सिंह और ओएसडी (शिक्षा), रंजना देसवाल के साथ वरिष्ठ अधिकारी, स्कूलों के प्रमुख, शिक्षक और छात्र उपस्थित थे।

एनडीएमसी स्कूल के छात्रों के नए पाठ्यक्रम की पहल का अनावरण करने के बाद, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शिक्षक हमारे राष्ट्र के सच्चे चित्रकार हैं - आज बच्चों में वे जो मूल्य डालते हैं, वे भारत के कल के जीवंत कैनवास को आकार देंगे। जिस प्रकार देखभाल से पोषित बीज एक शक्तिशाली वट वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार शिक्षक युवा मन में जो ज्ञान और मूल्य बोते हैं, वे भविष्य के मजबूत, जिम्मेदार नागरिकों के रूप में विकसित होते हैं।

उन्होंने कहा कि बच्चों को नदियों, जंगलों, पहाड़ों और जल के संरक्षण का महत्व सिखाना हमारा पवित्र कर्तव्य है। तभी हम प्राकृतिक संसाधनों की अमूल्य विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचा सकते हैं। उन्होंने शहर को स्वच्छ, हरा-भरा और सुंदर बनाए रखने के प्रयासों के लिए एनडीएमसी की सराहना की और कहा कि पूरी दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, हमें सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को साकार करना होगा - पानी की हर बूँद बचाना, प्रदूषण से लड़ना और यमुना को उसकी प्राचीन गरिमा प्रदान करना इनमें शामिल है।

दिल्ली सरकार के मंत्री - प्रवेश वर्मा ने एनडीएमसी को नए पाठ्यक्रम लागू करने पर बधाई देते हुए कहा कि एनडीएमसी अपने कार्यों में विकास के साथ-साथ विरासत मूल्यों को भी शामिल कर रही है, जिसका एक उदाहरण भारतीय वास्तुकला की झलक से निर्मित घंटाघर का शिलान्यास है।

उन्होंने कहा कि यमुना में बार-बार आने वाली बाढ़ का कारण यह है कि हमने अपनी नदियों को विरासत नहीं माना और इस दृष्टि से उनका रखरखाव व संरक्षण नहीं किया। यमुना को संरक्षित करने के लिए हमें उसे विरासत का महत्व देना होगा, तभी हम किसी नदी को किसी शहर की जीवन रेखा बना सकते हैं।

इस अवसर पर, सांसद (नई दिल्ली) - बांसुरी स्वराज ने शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक न केवल बच्चों को अपना समय देते हैं, बल्कि उन्हें सांस्कृतिक मूल्य भी देते हैं, जो आगे चलकर एक नई संस्कृति का निर्माण करते हैं। ये छात्र न केवल देश का भविष्य गढ़ रहे हैं, बल्कि वे देश की संस्कृति का भी विकास कर रहे हैं। ऐसी पहल ने देश की विरासत के साथ-साथ देश को भी जोड़ने का काम किया है।

एनडीएमसी अध्यक्ष - केशव चंद्रा ने कहा कि एनडीएमसी का यह ₹ विकास भी , विरासत भी ₹ पाठ्यक्रम - नई शिक्षा प्रणाली के तहत नए पाठ्यक्रम के साथ बदलाव की विरासत भी है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आदर्श वाक्य - ₹विकास भी, विरासत भी₹ के तहत, इस नए पाठ्यक्रम में योग, अंकगणित और प्राचीन ज्ञान परंपराओं को शामिल किया गया है। इसमें नई परंपरा और ज्ञान की शिक्षा भी साथ साथ दी जाएगी, जो विकसित भारत के कदमों के तहत भारतीय विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुँचाएगी।

इस अवसर पर एनडीएमसी के उपाध्यक्ष - कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने छात्र जीवन से ही शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग करने के लिए सदैव तत्पर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एनडीएमसी का पहला उद्देश्य प्रधानमंत्री की विकसित भारत की सोच और विचार को आगे बढ़ाने में मदद करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री के ₹विकास भी और विरासत भी₹ के अंतर्गत, सबसे पहले एनडीएमसी के नए पाठ्यक्रमों में पंच प्राण, प्रकृति से शिक्षा, योग, भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल किया गया है।

नए पाठ्यक्रम की पहल की विशेषताओं के बारे में बताते हुए चहल ने कहा कि एनडीएमसी स्कूलों के 28,000 से अधिक छात्र इस समग्र और मूल्य-आधारित शिक्षण मॉडल से लाभान्वित होंगे।

इस अवसर पर, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली ने अटल आदर्श और नवयुग स्कूलों के 15 उत्कृष्ट शिक्षकों/शिक्षाविदों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया, उनमें - मोनिका आनंद (प्रधानाचार्य), रमा जोशी (हेड मिस्ट्रेस), डॉ. रचना मोहन (पीजीटी अंग्रेजी), नरेश कुमार (पीजीटी कंप्यूटर साइंस), सीवेंद्र सिंह (पीजीटी इतिहास), देब डी. दत्ता (पीजीटी चित्रकला), कमलेश कुमारी (टीजीटी कार्य अनुभव), रेणु सचदेवा (टीजीटी प्राकृतिक विज्ञान), हरीश कुमार रावत (टीजीटी अंग्रेजी), वर्षा सिंह (टीजीटी अंग्रेजी), कैलाश चंद्र दक्ष (टीजीटी गणित), संजय कुमार यादव (सहायक शिक्षक), पारुल चौधरी (टीजीटी शारीरिक शिक्षा), एस. ग्लोरी मैरी (सहायक शिक्षक), सरोज (टीजीटी चित्रकला) शामिल है।

एनडीएमसी की ओएसडी (शिक्षा) - रंजना देसवाल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए एनडीएमसी द्वारा अपनाए गए नए पाठ्यक्रम के साथ भविष्य के विजन की व्याख्या की और कहा कि ₹विकास भी, विरासत भी₹ के साथ, हमें विश्वास है कि हम शिक्षा का एक ऐसा अनुकरणीय मॉडल तैयार कर पाएँगे, जो परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण होगा। हमें उम्मीद है कि यह पहल भारत भर के अन्य नगर निकायों, राज्य सरकारों और नागरिक संस्थानों को प्रेरित करेगी।

हिंदुस्तान की विदेश नीति : बदलते वैश्विक परिदृश्य में नई दिशा और चुनौतियाँ

अशोक कुमार झा

21वीं सदी की अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान का स्थान तेजी से बदल रहा है। एक ओर यह पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरी ओर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताक़त। इसकी 1.4 अरब से अधिक जनसंख्या, विशाल युवा शक्ति, मजबूत आईटी और अंतरिक्ष तकनीक, परमाणु क्षमता, रक्षा ताक़त और सांस्कृतिक धरोहर इसे वैश्विक मंच पर एक निर्णायक खिलाड़ी बनाते हैं।

लेकिन इस ऊँचाई के साथ-साथ चुनौतियाँ भी उतनी ही बड़ी हैं। बदलती वैश्विक राजनीति, चीन का उभार, अमेरिका-रूस का टकराव, आतंकवाद, जलवायु संकट और तकनीकी प्रतिस्पर्धा – इन सबके बीच हिंदुस्तान की विदेश नीति को संतुलन साधते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है।

1. विदेश नीति की ऐतिहासिक जड़ें

हिंदुस्तान की विदेश नीति की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। उन्होंने इसे असंपृक्त आंदोलन (Non-Aligned Movement) से जोड़ा। उनका मानना था कि शीत युद्ध के समय किसी एक गुट (अमेरिका या सोवियत संघ) के साथ पूरी तरह खड़े होने से हिंदुस्तान की स्वतंत्रता और स्वायत्तता सीमित हो जाएगी।

नेहरू युग : पंचशील सिद्धांत (1954) – आपसी सम्मान, संप्रभुता और हस्तक्षेप न करने के उसूल।

इंदिरा गांधी युग : बांग्लादेश मुक्ति संग्राम (1971), परमाणु परीक्षण (1974), और सोवियत संघ के साथ संधि।

राजीव गांधी युग : तकनीकी सहयोग और आधुनिक कूटनीति की शुरुआत।

अटल बिहारी वाजपेयी युग : 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण और अमेरिका से नए रिश्तों की नींव।

मनमोहन सिंह युग : 2005 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौता, आर्थिक वैश्वीकरण को गति।

नरेंद्र मोदी युग : आक्रामक, सक्रिय और व्यक्तित्व-प्रधान कूटनीति।

2. विदेश नीति के मूल तत्व

आज हिंदुस्तान की विदेश नीति केवल "सुरक्षा" तक सीमित नहीं बल्कि बहुआयामी है। इसके मुख्य तत्व हैं –

रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) : किसी एक ध्रुव पर निर्भर न रहकर संतुलन बनाना।

नेबरहुड फर्स्ट : पड़ोसी देशों के साथ प्राथमिकता से संबंध।

एक्ट ईस्ट : दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सक्रियता।

ग्लोबल साउथ का नेतृत्व : विकासशील देशों की आवाज़ उठाना।

डायस्पोरा डिप्लोमेसी : प्रवासी भारतीयों को विदेश नीति का हिस्सा बनाना।

सांस्कृतिक कूटनीति : योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और भारतीय सभ्यता के जरिए वैश्विक छवि गढ़ना।

3. पड़ोसी देशों के साथ संबंध

(क) पाकिस्तान :

सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद।

पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक ने नई नीति स्पष्ट की – "आतंकवाद का जवाब कूटनीति नहीं, सख्त कार्रवाई से।"

पाकिस्तान की अस्थिरता हिंदुस्तान के लिए सुरक्षा जोखिम है।

(ख) चीन :

सीमा विवाद (डोकलाम, गलवान संघर्ष)।

व्यापारिक निर्भरता – चीन से सबसे अधिक आयात।

हिंद महासागर और एशिया में शक्ति संतुलन की प्रतिस्पर्धा।

(ग) नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार :

"नेबरहुड फर्स्ट" नीति इन्हीं पर केंद्रित है।

नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता, श्रीलंका का आर्थिक संकट, म्यांमार में सेना का शासन – इन सबका असर सीधे हिंदुस्तान पर पड़ता है।

बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता और नदी जल बंटवारे का प्रश्न महत्वपूर्ण है।

4. वैश्विक महाशक्तियों के साथ संबंध

(क) अमेरिका :

हिंदुस्तान-अमेरिका संबंध आज "नेचुरल पार्टनरशिप" कहे जाते हैं।

QUAD (हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) – चीन को संतुलित करने की रणनीति।

प्रौद्योगिकी, रक्षा, 5G, अंतरिक्ष और व्यापार में साझेदारी।

(ख) रूस :

दशकों से रक्षा सहयोग का आधार।

यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी दबाव के बावजूद हिंदुस्तान ने रूस से सस्ता तेल खरीदा।

यह "राष्ट्रहित पहले" की नीति का उदाहरण है।

(ग) यूरोप :

फ्रांस हिंदुस्तान का प्रमुख रक्षा साझेदार (राफेल विमान)।

जर्मनी और ब्रिटेन के साथ भी आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग बढ़ रहा है।

5. पश्चिम एशिया और मध्य एशिया

खाड़ी देशों से ऊर्जा सुरक्षा (तेल और गैस आयात)।

80 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों का योगदान।

इजरायल और अरब देशों के बीच हिंदुस्तान की "संतुलनकारी भूमिका"।

ईरान के चाबहार बंदरगाह से हिंदुस्तान को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुँच।

6. हिंद महासागर और समुद्री रणनीति

हिंद महासागर को "21वीं सदी का खेल का मैदान" कहा जा रहा है।

चीन की बढ़ती उपस्थिति (String of Pearls रणनीति) को संतुलित करने के लिए हिंदुस्तान "SAGAR – Security and Growth for All in the Region" नीति पर काम कर रहा है।

अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और मालदीव जैसे क्षेत्रों में समुद्री ताक़त को मजबूत किया जा रहा है।

7. ग्लोबल साउथ और G20

हिंदुस्तान ने G20 अध्यक्षता के दौरान "ग्लोबल साउथ" को मंच दिया।

जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, ऋण संकट और डिजिटल अंतराल जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों की आवाज़ बुलंद की।

यह विदेश नीति का नया आयाम है, जिससे हिंदुस्तान "नेतृत्वकारी शक्ति" के रूप में उभरा है।

8. प्रवासी भारतीय और सांस्कृतिक कूटनीति

अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, खाड़ी देशों और अफ्रीका में करोड़ों प्रवासी भारतीय रहते हैं।

वे न केवल धन भेजते हैं, बल्कि हिंदुस्तान की सकारात्मक छवि भी बनाते हैं।

योग दिवस (21 जून) को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता मिलना, आयुर्वेद और बॉलीवुड की लोकप्रियता – ये सब सांस्कृतिक कूटनीति के उदाहरण हैं।

9. भविष्य की चुनौतियाँ

चीन-अमेरिका टकराव में संतुलन।

आतंकवाद और साइबर हमले।

जलवायु संकट और ऊर्जा सुरक्षा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी प्रतिस्पर्धा।

संयुक्त राष्ट्र सुधार और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की लड़ाई।

10. निष्कर्ष

हिंदुस्तान की विदेश नीति अब रक्षात्मक से आक्रामक और प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय हो चुकी है। यह नीति स्पष्ट रूप से "राष्ट्रहित सर्वोपरि" के सिद्धांत पर टिकी है।

आज हिंदुस्तान केवल दक्षिण एशिया की शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। अगर यह नीति संतुलन, दूरदर्शिता और व्यावहारिकता के साथ आगे बढ़ी तो आने वाले दशकों में हिंदुस्तान न केवल "विकासशील दुनिया की आवाज़" रहेगा बल्कि वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा।

दिल्ली भाजपा ने पहले नवरात्र से जी.एस.टी. में राहत की घोषणा का स्वागत किया

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने जी.एस.टी. दर स्लैब घटाने और लाइफ एवं हेल्थ इंश्योरेंस से जी.एस.टी. हटाने पर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होने कहा है की यह जी.एस.टी. रिफॉर्म प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरगामी विज़न का भाग, यह भारतीय उधोग को बढ़ावा देंगे और भारत को विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयास का निर्णायक कदम है। वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की पहले नवरात्र 22 सितम्बर से जी.एस.टी. दर स्लैब घटाने से जहां उपयोक्ताओं को सस्ता समान मिलेगा वहीं यह कदम कर चोरी की समस्या का भी अंत करेगी।

दिल्ली के मध्यम वर्ग को लाइफ एवं हैलथ इंश्योरेंस से जी.एस.टी. हटने से बड़ी राहत मिलेगी। इसी तरह प्राइमरी शिक्षा से जुड़ी शिक्षा सामग्री पर जी.एस.टी. माफ होने से गरीब ही नही मध्यम वर्ग को भी लाभ होगा।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ़ इंडिया यूनियन के तत्वाधान में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

मुख्य संवाददाता

दिल्ली: "मेरा मीडिया परिवार" की अवधारणा को ध्यान में रखकर, वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनियन, 6 सितंबर, 2025 को, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से , मीडियाकर्मियों व उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक दिन का स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन कर रहा है । वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ़ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी ने जानकारी देते हुए यह बताया कि ये कैंप बाबा खड्ग सिंह रोड पर गुरुद्वारा बंगला साहब स्थित पैथ लैब में आयोजित किया जा रहा है। यूनियन का मानना है कि दिल्ली के इतिहास में इस तरह का भव्य ,स्वास्थ्य जांच शिविर न कभी लगा था । कैंप में डॉक्टर निःशुल्क देखेंगे, सभी टेस्ट निःशुल्क होंगे व दवाईयों भी निःशुल्क मिलेंगी । कैंप सुबह 9,30 बजे शुरू हो जाएगा जो 2 बजे तक चलेगा । बेहतर होगा कि कैंप में खाली पेट आए, यदि किसी का भी पहले से कोई इलाज चल रहा है, तो उसे जुड़े सभी मेडिकल पेपर लेकर आए । लंगर की भी व्यवस्था है । अधिक जानकारी के लिए कैंप संयोजक देवेंद्र पवार (8130756062) , कैंप सह संयोजक स्वतंत्र सिंह भुल्लर (9811332377) से संपर्क करे।

डिजिटल युग में शिक्षक की भूमिका हुई और अधिक महत्वपूर्ण

-संदीप सृजन

डिजिटल युग ने शिक्षा के परिदृश्य को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है। पहले शिक्षक कक्षा में ब्लैकबोर्ड और पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करते थे किन्तु आज वे डिजिटल उपकरणों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ऑनलाइन मंचों के साथ मिलकर छात्रों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। आज जब हम डिजिटल परिवर्तन के शिखर पर हैं, शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान वितरक से बदलकर मार्गदर्शक, परामर्शदाता और नवप्रवर्तक की हो गई है। आज शिक्षक डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर शिक्षा को अधिक समावेशी, व्यक्तिगत और प्रभावशाली बना रहे हैं।

डिजिटल युग की शुरुआत इंटरनेट और कंप्यूटर के प्रसार से हुई परन्तु 2020 की कोविड-19 महामारी ने इसे तीव्र गति प्रदान की। ऑनलाइन कक्षाएँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने शिक्षा को घर-घर तक पहुँचाया। युनेस्को की सन्-2025 की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व भर में 80% से अधिक छात्र डिजिटल उपकरणों से जुड़े हैं। इस परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका केंद्रीय है। वे अब केवल लेक्चर देने वाले नहीं, अपितु डिजिटल सामग्री निर्माता (कंटेंट क्रिएटर) हैं जो वीडियो,इंटरएक्टिव क्विज और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से, शिक्षा हमेशा तकनीकी प्रगति से प्रभावित रही है। प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली मौखिक थी, मध्ययुग में पुस्तकों का आगमन हुआ और अब डिजिटल युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन शिक्षण ने क्रांति ला दी है। ओईसीडी की हाल की रिपोर्ट में उल्लेख है कि शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है, ताकि वे छात्रों को जोखिमों से बचाते हुए लाभ प्रदान कर सकें।

डिजिटल युग में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका मार्गदर्शक की है। वे छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित और निर्देशित करते हैं, न कि केवल सूचना प्रदान करते हैं। आज फ्लिप्ड क्लासरूम में छात्र घर पर वीडियो देखते हैं और कक्षा में विचार-विमर्श करते हैं। शिक्षक यहाँ मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, जो छात्रों की जिज्ञासा को सही दिशा देते हैं। दूसरी भूमिका परामर्शदाता की है। डिजिटल युग में सूचनाओं की प्रचुरता के बावजूद, छात्रों को सही दिशा की आवश्यकता होती है। शिक्षक व्यक्तिगत शिक्षण पथ तैयार करते हैं, जहाँ एआई के माध्यम से छात्र की कमजोरियों का विश्लेषण होता है और शिक्षक व्यक्तिगत फीडबैक प्रदान करते हैं। तीसरी भूमिका नवप्रवर्तक की है। शिक्षक डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर नवीन शिक्षण विधियाँ विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से इतिहास की घटनाओं को जीवंत करना या खेल- आधारित शिक्षण द्वारा गणित सिखाना। एक अध्ययन के अनुसार डिजिटल मंच शिक्षकों के ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देते हैं जिससे वे वैश्विक स्तर पर सहयोग कर पाते हैं।

डिजिटल युग में शिक्षकों के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और उपकरणों की कमी के कारण छात्र पिछड़ जाते हैं। युनेस्को के अनुसार, सन्-2025 में भी विकासशील देशों में 40% शिक्षक डिजिटल उपकरणों से अपरिचित हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, किन्तु कई देशों में यह अपर्याप्त है। ओईसीडी की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षकों को सक्षम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चुनौती साइबर सुरक्षा और गोपनीयता की है। ऑनलाइन कक्षाओं में डेटा लीक का खतरा रहता है। शिक्षकों को छात्रों को साइबर धमकी से बचाने की आवश्यकता है। साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से साहित्यिक चोरी बढ़ सकती है, जिसके लिए शिक्षकों को मूल्यांकन विधियों में परिवर्तन करना पड़ता है। अनिच्छुक शिक्षकों को प्रौद्योगिकी अपनाने में सहायता की आवश्यकता है।

मानसिक स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। डिजिटल कक्षाएँ शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं, जैसे 24 घण्टे उपलब्धता। एक अध्ययन के अनुसार, कई शिक्षक कार्यभार के कारण तनावग्रस्त हो रहे हैं। चुनौतियों के बावजूद, डिजिटल युग शिक्षकों के लिए अवसरों से परिपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षकों को नियमित कार्यों, जैसे ग्रेडिंग या लेसन प्लानिंग से मुक्त करती है जिससे वे रचनात्मकता पर ध्यान दे सकें। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग (सीओएल) की सन्-2025 की रिपोर्ट में उल्लेख है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षकों को सशक्त बनाती है। उदाहरण के लिए एआई टूल्स छात्रों की प्रगति का अनुसरण करते हैं और शिक्षकों को अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी शिक्षा को गहन बनाते हैं। शिक्षक वर्चुअल टूर्स आयोजित करते हैं, जैसे मंगल ग्रह की सैर या ऐतिहासिक घटनाओं का अनुभव। अमेरिकन एसपीसीसी के अनुसार डिजिटल युग में शिक्षा का विकास हो रहा है जहाँ शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं।

व्यक्तिगत शिक्षण एक बड़ा अवसर है। डिजिटल उपकरण छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री अनुकूलित करते हैं। शिक्षक डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर छात्रों की सहायता करते हैं। लिंक्डइन के एक लेख में सन्-2025 में एआई-पावर्ड क्लासरूम्स की चर्चा है, जहाँ शिक्षक एआई को सहायक के रूप में उपयोग करते हैं। वैश्विक स्तर पर, नाइजीरिया जैसे देशों में टीआरसीएन डिजिटल पोर्टल शुरू कर शिक्षकों को आधुनिक बना रहा है। भारत में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 डिजिटल शिक्षा पर बल देती है। शिक्षक दिक्षा और स्वयं जैसे मंचों का उपयोग करते हैं। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमी जैसी चुनौतियाँ हैं। सन्-2025 में, भारतीय शिक्षक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत कर रहे हैं परन्तु प्रशिक्षण की कमी एक बाधा है।

कुछ समय में शिक्षक की भूमिका और अधिक विकसित होगी। मेटावर्स में आभासी कक्षाएँ (वर्चुअल क्लासरूम्स) होंगी, जहाँ छात्र अवतार के रूप में भाग लेंगे। शिक्षक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ सहयोग करेंगे, किन्तु मानवीय संपर्क का महत्व बना रहेगा। एनसी स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग में शिक्षकों का मानवीय संबंध अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

शिक्षक दिवस विशेष

शिक्षक तो अनमोल है

नूर तिमिर को जो करें, बांटे सच्चा ज्ञान !
मिट्टी को जीवंत करें, गुरुवर वो भगवान !!

भरें प्रतिभा, योग्यता, बुनता सभ्य समाज !
समदृष्टि, सद्भाव भरें, पूजनीय ऋषिराज !!

जब रिश्ते हैं टूटते, होते विफल विधान !
गुरुवर तब सम्बल बने, होते बड़े महान !!

धैर्य और विवेक भरें, करते दुर्गुण दूर !
तप, बल से निर्मित करें, सौरभ निर्भय शूर !!

नानक, गौतम, द्रोण सँग, कौटिल्य संदीप !
अपने- अपने दौर के, मानवता के दीप !!

चाहत को पर दे यही, स्वप्न करे साकार !
शिक्षक अपने ज्ञान से, जीवन देत निखार !!

शिक्षक तो अनमोल है, इसको कम ना तोल !
मीठे हैं परिणाम बहुत, कड़वे इसके बोल !!

गागर में सागर भरें, बिखराये मुस्कान !
सौरभ जिसे गुरू मिले, ईश्वर का वरदान !!

डॉ. सत्यवान सौरभ

अनाम तपस्वी

शिक्षक वही है
जो शिष्य को यह न सिखाए कि क्या सोचना है,
बल्कि यह सिखाए कि कैसे सोचना है।
जो बच्चों की जिज्ञासा को दबाए नहीं,
बल्कि प्रश्नों को पंख दे।
जो उन्हें अनुशासन की कठोरता में नहीं,
बल्कि संवेदनशीलता की कोमलता में गढ़े।

शिक्षक दीपक की भाँति है,
जो स्वयं जलकर
अनगिनत जीवनों में उजाला भरता है।
वह अनाम तपस्वी है,
जिसकी थकान उसके शिष्यों की सफलता में
गायब हो जाती है।
वह वह संगीत है,
जो मौन रहकर भी
जीवन के हर कोने को स्वर से भर देता है।

शिक्षक केवल ज्ञान का वितरक नहीं,
वह तो आत्मा का माली है,
जो जिज्ञासा की कली को
संस्कारों की धूप और संवेदनाओं की वर्षा से
खिलाता है।
डिग्रियाँ जीवन नहीं गढ़तीं,
जीवन तो शिक्षक की मुस्कान गढ़ती है।

वह सिखाता है—
सत्य क्या है, साहस क्या है,
और करुणा क्या है।
मशीनें सूचना दे सकती हैं,
परंतु शिक्षक ही इंसान बना सकता है।
इसीलिए कहा गया है—
"गुरु देवो महेश्वर"।
बदलते समय में भी गुरु का अर्थ अनमोल है,
क्योंकि वही है,
जो अंधकार से प्रकाश तक ले जाता है।

---डॉ प्रियंका सौरभ

शिक्षक दिवस विशेष : "किताबों से स्क्रीन तक: बदलते समय में गुरु का असली अर्थ"

डिजिटल युग में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। किताब से लेकर स्क्रीन तक की यह यात्रा ज्ञान तो दे रही है, लेकिन संस्कार और मानवीय मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं। ऐसे समय में शिक्षक का महत्व और भी बढ़ जाता है। शिक्षक ही वह पुल हैं जो बच्चों को वर्तमान से जोड़कर सुरक्षित भविष्य तक पहुँचाते हैं। मशीनें जानकारी दे सकती हैं, परंतु संवेदनशीलता और चरित्र निर्माण केवल गुरु ही कर सकता है। इस शिक्षक दिवस पर संकल्प यही हो कि तकनीक की दौड़ में संस्कारों की नदियाँ कभी सूखने न पाएं।

- डॉ. प्रियंका सौरभ

शिक्षक दिवस केवल एक औपचारिक अवसर नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र की आत्मा को समझने का दिन है। जब भी हम गुरु या शिक्षक का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा व्यक्तित्व उभरता है, जो केवल पढ़ाने वाला नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला होता है। भारतीय संस्कृति में शिक्षक को 'आचार्य' कहा गया है, जिसका अर्थ है आचरण से शिक्षा देने वाला। इसी दृष्टि से देखा जाए तो आज के दौर में शिक्षकों की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, क्योंकि यह वह समय है जब तकनीक और स्क्रीन बच्चों की सोच और संवेदनाओं को प्रभावित कर रही है।

आज से कुछ दशक पहले शिक्षा का स्वरूप केवल पुस्तकों, कक्षा और संवाद तक सीमित था। विद्यार्थी शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते थे और वही बातें उनके जीवन का आधार बनती थीं। लेकिन डिजिटल क्रांति ने इस परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। मोबाइल फोन, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बढ़ते प्रभाव ने विद्यार्थियों के लिए अनगिनत अवसर तो खोले हैं, परंतु इसके साथ ही कई चुनौतियाँ भी खड़ी की हैं। जानकारी का महासागर अब हर बच्चे की उंगलियों पर उपलब्ध है, परंतु उसी महासागर में गलत जानकारी, भ्रामक सामग्री और असीमित मनोरंजन का जाल भी बिछा है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि इस विशाल और असंतुलित सूचना-संसार में बच्चों को सही मार्ग कौन दिखाएगा? इसका उत्तर है – शिक्षक।

शिक्षक की भूमिका अब केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित नहीं रह गई है। वह एक मार्गदर्शक, मूल्यनिर्माता और व्यक्तित्व निर्माता है। जब बच्चा मोबाइल पर स्क्रीन की दुनिया में खोया रहता है, तब शिक्षक का दायित्व है कि वह उसे वास्तविक जीवन की चुनौतियों से परिचित कराए। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री पाना या नौकरी करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी होना चाहिए कि बच्चा समाज का जिम्मेदार नागरिक बने, उसमें करुणा, संवेदनशीलता और विवेक विकसित हो।

शिक्षक ही वह कड़ी है जो घर और समाज के बीच संतुलन कायम करता है। घर बच्चे को प्यार और संस्कार देता है, लेकिन उन्हें स्थायी बनाने का काम शिक्षक करता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को केवल गणित या विज्ञान नहीं पढ़ाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है, असफलताओं से कैसे सीखना है और जीवन में ईमानदारी तथा सत्य का महत्व क्या है।

आज की शिक्षा प्रणाली पर विचार करें तो हम पाते हैं कि इसमें प्रतिस्पर्धा और अंकों की दौड़ हावी हो गई है। बच्चे अधिक अंक लाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, अभिभावक भी उन्हें उसी दिशा में धकेलते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में मानवीय मूल्यों की नींव कमजोर हो रही है। यही कारण है कि समाज में आत्मकेंद्रित प्रवृत्तियाँ, नैतिक पतन और संवेदनहीनता बढ़ रही है। इस कमी को दूर करने वाला कोई है तो वह शिक्षक ही है। शिक्षक यदि चाहे तो बच्चों में सहयोग, सेवा, सहानुभूति और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित कर सकता है।

स्क्रीन का प्रभाव इतना गहरा हो गया है कि बच्चे वास्तविक संवाद से दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वे हजारों मित्र बना लेते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। इस स्थिति से बाहर निकालने का काम केवल शिक्षक कर सकता है। कक्षा में जब शिक्षक बच्चों से संवाद करता है, तो वह केवल पढ़ाने का कार्य नहीं करता, बल्कि बच्चों की भावनाओं को भी छूता है। एक सच्चा शिक्षक वही है जो विद्यार्थियों को यह महसूस कराए कि वे महत्वपूर्ण हैं, उनकी समस्याएँ सुनी जाती हैं और उनका मार्गदर्शन किया जाएगा।

शिक्षक का महत्व केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है। राष्ट्रनिर्माण में शिक्षक की भूमिका अत्यंत निर्णायक होती है। यह कहावत बार-बार दोहराई जाती है कि किसी देश का भविष्य उसके कक्षाओं में गढ़ा जाता है। यह कथन केवल आदर्श नहीं है, बल्कि कठोर सत्य है। यदि कक्षाओं में अच्छे शिक्षक होंगे, जो बच्चों को नैतिकता, ज्ञान और आत्मविश्वास से भरेंगे, तो वही बच्चे आगे चलकर अच्छे नागरिक, नेता, वैज्ञानिक और प्रशासक बनेंगे। लेकिन यदि शिक्षक केवल परीक्षा पास कराने तक सीमित रह गया, तो समाज का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

आज आवश्यकता है कि शिक्षक स्वयं को भी समयानुकूल बनाएं। तकनीक से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसे सकारात्मक ढंग से अपनाना जरूरी है। शिक्षक यदि चाहे तो स्क्रीन और डिजिटल माध्यमों को शिक्षा के सहयोगी बना सकता है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, शैक्षिक वीडियो, वर्चुअल प्रयोगशालाएँ और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकें बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ा सकती हैं। लेकिन इन सबके बीच मानवीय संवाद की जगह कोई नहीं ले सकता। मशीनें ज्ञान दे सकती हैं, परंतु संस्कार और संवेदनशीलता केवल शिक्षक ही दे सकता है।

शिक्षक दिवस पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शिक्षक का सम्मान केवल औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित न रहे। यह सम्मान तभी सार्थक होगा जब हम उन्हें उचित सुविधाएँ, प्रशिक्षण और प्रेरणादायक वातावरण दें। आज भी कई शिक्षक सीमित संसाधनों में चमत्कार कर रहे हैं। वे अपने विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त समय निकालते हैं, नई विधियाँ खोजते हैं और बच्चों के जीवन को संवारते हैं। ऐसे शिक्षकों को न केवल प्रणाम करना चाहिए, बल्कि उनकी मेहनत को राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति मानना चाहिए।

महान दार्शनिक और शिक्षक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षक ही समाज की आत्मा होते हैं। उनकी शिक्षाएँ पीढ़ियों को प्रभावित करती हैं और उनके व्यक्तित्व से आने वाली रोशनी दूर-दूर तक फैलती है। आज जब हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने शिक्षकों का सम्मान करेंगे, उनकी भूमिका को और सशक्त बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ केवल जानकारी ही नहीं, बल्कि विवेक, संवेदनशीलता और संस्कार भी हासिल करें।

त्यौहार: मेरी नज़र से - दिवाली

त्यौहार, मेरे लिए, सिर्फ़ कैलेंडर पर अंकित एक तारीख नहीं होते। ये जीवन की एक जीवंत धड़कन हैं, जो हमें रोज़मर्रा की भाग-दौड़ से निकालकर एक पल रुककर साँस लेने का मौका देते हैं। ये वो रंग हैं, जो जीवन की सफ़ेद-काली तस्वीर में नई जान भर देते हैं। मेरी नज़र में, दिवाली इन्हीं रंगों और धड़कनों का सबसे ख़ूबसूरत संगम है। यह सिर्फ़ दीपों का नहीं, बल्कि दिलों का त्यौहार है।

दिवाली की शुरुआत मेरे लिए हफ़्तों पहले ही हो जाती है। घर की साफ़-सफ़ाई के साथ-साथ मन की भी सफ़ाई शुरू हो जाती है। यह एक मौका होता है, जब हम अपने घर के हर कोने को चमकाते हैं, पुराने सामान को हटाते हैं और एक नई शुरुआत के लिए जगह बनाते हैं। यह सिर्फ़ बाहरी सफ़ाई नहीं है, बल्कि एक तरह का आंतरिक शुद्धिकरण है। जब घर के हर कोने से धूल हटती है, तो मन से भी पुरानी शिकायतें और गिले-शिकवे दूर होने लगते हैं।

दिवाली का सबसे प्यारा पहलू है, इसका सामाजिक ताना-बाना। यह वो समय है, जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ आते हैं। दूर-दराज रहने वाले भाई-बहन, रिश्तेदार और दोस्त सब एक छत के नीचे इकट्ठा होते हैं। पकवानों की ख़ुशबू, बच्चों की हँसी और बड़ों की बातें, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं, जिसकी तुलना किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती। यही वो पल हैं, जब हम अपनी परंपराओं और जड़ों से फिर से जुड़ते हैं।

शाम होते ही घर रोशनी से जगमगा उठता है। मिट्टी के छोटे-छोटे दीयों की रोशनी में एक अलग ही सुकून होता है। ये दिए सिर्फ़ घर को रोशन नहीं करते, बल्कि अँधेरे पर रोशनी की जीत का संदेश देते हैं। पटाखों का शोर और आसमान में रंग-बिरंगी आतिशबाज़ी भले ही कुछ देर के लिए मन को ख़ुश करती है, लेकिन मेरे लिए असली दिवाली तो घर के दरवाज़े पर जलते दीयों और उन पर पड़ने वाली परछाइयों में है।

मेरे लिए दिवाली का मतलब सिर्फ़ लक्ष्मी-गणेश की पूजा करना नहीं है, बल्कि उस भावना को महसूस करना है जो इस पूजा के पीछे है। लक्ष्मी यानी समृद्धि और गणेश यानी ज्ञान। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि जीवन में समृद्धि तभी आती है, जब हम ज्ञान और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह सिर्फ़ धन की नहीं, बल्कि रिश्तों की, ख़ुशियों की और सद्भाव की समृद्धि का त्यौहार है।

दिवाली का सबसे ख़ूबसूरत हिस्सा होता है, मिठाइयों और उपहारों का आदान-प्रदान। यह सिर्फ़ खाने की चीज़ें नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान का प्रतीक हैं। जब हम अपने पड़ोसियों और दोस्तों के घर मिठाई लेकर जाते हैं, तो हम उनके साथ अपनी ख़ुशियाँ भी बाँटते हैं। यही बाँटना और साझा करना ही इस त्यौहार की असली आत्मा है।

आख़िर में, मेरे लिए दिवाली एक त्यौहार नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ क्यों न हों, रोशनी हमेशा अँधेरे को दूर कर सकती है। यह सिर्फ़ एक रात का जश्न नहीं, बल्कि एक ऐसी सीख है, जो हमें साल भर याद रखनी चाहिए - हमेशा उम्मीद की एक किरण जलाए रखें।

सत्यम मिश्रा

'अध्यात्म प्रखर लेखनी सम्मान 2025' से अलंकृत हुए डॉ. गोपाल चतुर्वेदी

प्राग हरि साहित्यिक व आध्यात्मिक शोध संस्थान, जयपुर एवं ब्रजवानी जन सेवा समिति, ब्रज नगर (डीग) राजस्थान ने संयुक्त रूप से किया डॉ. गोपाल चतुर्वेदी का सम्मान

मथुरा। ट्रांसपोर्ट नगर/मंडी समिति के पीछे मंशा टीला स्थित पं लटूर प्रधान फार्म हाउस में प्राग हरि साहित्यिक व आध्यात्मिक शोध संस्थान, जयपुर एवं ब्रजवानी जन सेवा समिति, ब्रज नगर (डीग) राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में राधाष्टमी के पावन अवसर पर संपन्न हुए साहित्यकार सम्मान समारोह में नगर के प्रख्यात साहित्यकार, अध्यात्मविद् व पत्रकार डॉ. गोपाल चतुर्वेदी, एडवोकेट का उनकी लेखनी के द्वारा धर्म, अध्यात्म व ब्रज संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए सम्मान किया गया।साथ ही उन्हें ₹अध्यात्म प्रखर लेखनी सम्मान - 2025₹ से अलंकृत किया गया।यह सम्मान उन्हें प्राग हरि साहित्यिक और आध्यात्मिक शोध संस्थान की संस्थापक अध्यक्ष साहित्य पद्मश्री साध्वी प्रोफेसर डॉ. सरोज गुप्ता (जयपुर) व ब्रजवानी जन सेवा समिति के अध्यक्ष हरीश चंद्र शर्मा ₹हरि₹ ने प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र एवं ठाकुरजी का पटुका-प्रसादी माला आदि भेंट करके किया।

प्राग हरि साहित्यिक और आध्यात्मिक शोध संस्थान की संस्थापक अध्यक्ष साहित्य पद्मश्री साध्वी प्रोफेसर डॉ. सरोज गुप्ता ने कहा कि वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. गोपाल चतुर्वेदी के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रज सम्बन्धी उत्कृष्ट लेखन के क्षेत्र में अनेकों कीर्तिमान हैं।हम सभी उन्हें सम्मानित करके स्वयं को गौरांवित अनुभव कर रहे हैं।साथ ही ठाकुरजी से उनकी उत्तरोत्तर प्रगति एवं सुखद व समृद्ध जीवन की मंगल कामना करते हैं।

ब्रजवानी जन सेवा समिति के अध्यक्ष हरीश चंद्र शर्मा ₹हरि₹ ने कहा कि प्रख्यात साहित्यकार, अध्यात्मविद् व पत्रकार डॉ. गोपाल चतुर्वेदी, एडवोकेट धर्म व अध्यात्म जगत की बहुमूल्य विभूति हैं।वर्तमान में वे समाज सेवा के अलावा धर्म-अध्यात्म, साहित्य सृजन, हिन्दी व अंग्रेजी पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में पूर्ण समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

इस अवसर पर ओम प्रकाश पांडेय ₹निर्भय₹, डॉक्टर ब्रज भूषण चतुर्वेदी, कन्हैया लाल सारस्वत, प्रख्यात कवि अभिषेक ₹अमर₹, डॉ. आर.के. पाण्डेय, सोहनलाल प्रेम, नानकचंद ₹नवीन₹, भुवनेश चौहान ₹चिंतन₹, सबरस मुरसानी, श्याम सिंह मधुर जघीना, विनीता गौतम, श्रीमती रेनू उपाध्याय, हिमांशु भारद्वाज ₹नीतू₹, प्रतीक्षा सुहानी, राजेन्द्र अनुरागी, आचार्य निर्मल, लोकेश सिंघल एवं डॉ. राधाकांत शर्मा आदि की उपस्थिति विशेष रही।

शिक्षक दिवस और ईद-ए-मिलाद का अनूठा संगम 5 सितंबर 2025- भारतीय संस्कृति और वैश्विक सद्भाव का प्रतीक

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर भारत विविधताओं का देश है जहाँ भाषाएँ, धर्म, संस्कृतियाँ,परंपराएँ और विचारधाराएँ एक साथ मिलकर सह-अस्तित्व का अद्भुत उदाहरण पेश करती हैं।5सितंबर 2025 का दिन इस सांस्कृतिक विविधता को और भी गहराई से महसूस करने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि इस दिन शिक्षक दिवस और ईद-ए- मिलादउन -नबी दोनों एक साथ मनाए जा रहे हैं। यह केवल कैलेंडर का संयोग भर नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के उस ताने-बाने का प्रमाण है जिसमें विभिन्न आस्थाएँ और मान्यताएँ एक ही मंच पर आकर सामंजस्य और भाईचारे का संदेश देती हैं। मैं एडवोकेट किशन समुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र अपनी राइस सिटी के नाम से मशहूर गोंदिया सिटी में जब एक ही दिन आने वाले हैं दोनों पर्वों की तैयारी स्थलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग क़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इस विषय पर आर्टिकल लिखने की सोची।भारत के इतिहास में कई ऐसे अवसर आते रहे हैं जब अलग-अलग समुदायों के पर्व एक ही दिन पड़े हों। इसने हमेशा भारतीय लोकतंत्र और समाज की बहुलतावादी संरचना को मज़बूत किया है। 5 सितंबर 2025 का यह संगम भी इसी श्रंखला का हिस्सा है। जहाँ एक ओर शिक्षा और ज्ञान के महत्व को रेखांकित करने वाला शिक्षक दिवस है,वहीं दूसरी ओर करुणा, नैतिकता और पैग़म्बर मुहम्मद साहब की शिक्षाओं को स्मरण कराने वाला ईद-ए-मिलाद-उन- नबी है। यह दो अलग-अलग आयामों के उत्सव हैं,किंतु दोनों ही मानवता के कल्याण और समाज के उत्थान से जुड़े हैं।

साथियों बात अगर हम शिक्षक दिवस व ईद-ए-मिलाद- उन-नबी का निर्धारण और महत्व की करें तो,शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। उन्होंने शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन का साधन न मानकर, बल्कि जीवन और समाज को सही दिशा देने वाला स्तंभ बताया।उनकेअनुसार शिक्षक केवल पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता होता है।1962 से हर वर्ष यह दिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि शिक्षकों के योगदान को सम्मान दिया जा सके। यह परंपरा शिक्षा और ज्ञान की महत्ता को रेखांकित करती है और समाज में गुरु-शिष्य परंपरा की गरिमा को बनाए रखती है।दूसरी ओर, ईद-ए-मिलाद-उन- नबी इस्लामी चंद्र कैलेंडर के अनुसार तय होता है। इसे पैग़म्बर मुहम्मद साहब के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय पैग़म्बर की शिक्षाओं, उनके जीवन-दर्शन और मानवता के लिए दिए गए मार्गदर्शन को याद करता है। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि इंसानियत, बराबरी और करुणा का संदेश भी देता है। चूँकि यह पर्व चंद्र कैलेंडर पर आधारित है, इसलिए हर वर्ष इसकी तिथि बदलती रहती है।संयोगवश 2025 में यह 5 सितंबर को पड़ रहा है, जो इसे और भी विशेष बना देता है।

साथियों बात अगर हम दोनों दोनों पर्वों के संयोग क़े ऐतिहासिक पहलू की करें तो, इतिहासकारों और धार्मिक विद्वानों के अनुसार, संभवतः पहली बार ऐसा अवसर आया है जब भारत का शिक्षक दिवस और इस्लामी जगत का ईद-ए-मिलाद-उन-नबी एक ही दिन मनाया जा रहा है। यह अद्वितीय संयोग भारत की सांस्कृतिक धरती की विशेषता को दर्शाता है। भारतीय समाज हमेशा से विभिन्न समुदायों के मेल-जोल का प्रतीक रहा है, और यह घटना उसी परंपरा की एक नई झलक प्रस्तुत करती है।

साथियों बातें अगर हम दोनों पर्वों शिक्षा और धर्म क़े साझा संदेश क़ी करें और इसे यदि हम गहराई से देखें तो शिक्षक दिवस और ईद-ए-मिलाद दोनों का मूल संदेश एक ही है, ज्ञान, नैतिकता और मानवता की सेवा। डॉ. राधाकृष्णन ने शिक्षा को राष्ट्र और मानवता के विकास की आधारशिला माना, वहीं पैग़म्बर मुहम्मद साहब ने इंसानियत, भाईचारे और समानता को सबसे महत्वपूर्ण बताया। इस तरह, दोनों पर्व हमें सिखाते हैं कि चाहे शिक्षा के माध्यम से हो या धर्म के माध्यम से, लक्ष्य हमेशा इंसान को बेहतर बनाना और समाज में शांति व न्याय स्थापित करना ज़रूरी है।

साथियों बातें कर हमअंतरराष्ट्रीय स्तरपर यह संगम और भी महत्वपूर्ण है होने की करें तो, आज पूरी दुनियाँ धार्मिक असहिष्णुता, सांप्रदायिक टकराव और सांस्कृतिक विभाजन की चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में भारत से यह संदेश जाता है कि विभिन्न धर्म और परंपराएँ एक साथ मिलकर मनाई जा सकती हैं और समाज में भाईचारा स्थापित किया जा सकता है। यह केवल भारतीय लोकतंत्र की शक्ति ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति की दिशा में भी एक प्रेरक उदाहरण है।शिक्षक दिवस और ईद-ए- मिलाद का साझा उत्सव व सामाजिक प्रयोग हैं

भारत के कई राज्यों में 5 सितंबर 2025 को विद्यालयों, कॉलेजों और मस्जिदों दोनों में उत्सव का माहौल रहेगा। बच्चे अपने शिक्षकों का सम्मान करेंगे और मुस्लिम समाज पैग़म्बर साहब की शिक्षाओं को याद करेगा। यह दृश्य उस सामाजिक प्रयोग जैसा होगा जहाँ दो अलग- अलग मान्यताएँ एक-दूसरे के साथ विरोध में नहीं, बल्कि सहयोग में खड़ी होती हैं। इससे समाज में आपसी सम्मान और विश्वास बढ़ता है।

साथियों बात अगर हम अवकाश का प्रश्न,राष्ट्रीय और राजपत्रित छुट्टियाँ बहुसांस्कृतिकता का जीवंत उदाहरण की करें तो, ध्यानt देने योग्य तथ्य यह है कि न तो शिक्षक दिवस और न ही ईद-ए-मिलाद भारत में राष्ट्रीय अवकाश की श्रेणी में आते हैं।हालाँकि ईद-ए-मिलाद को राजपत्रित अवकाश माना जाता है, यानी केंद्र सरकार इसेमान्यता देती है और राज्यों को यह अधिकार होता है कि वे अपने स्तर पर छुट्टी घोषित करें। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में यह दिन सरकारी अवकाश होता है। इसके विपरीत, शिक्षक दिवस को प्रायः शैक्षिक संस्थानों में ही विशेष कार्यक्रमों और समारोहों के रूप में मनाया जाता है, जबकि औपचारिक अवकाश नहीं होता। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान और प्रशासन दोनों ही विभिन्न आस्थाओं को सम्मान देते हुए लचीलेपन की नीति अपनाते हैं।भारत की शक्ति हमेशा उसकी बहुसांस्कृतिकता में रही है। यहाँ एक ओर हिन्दू पर्व दीपावली और होली हैं, तो दूसरी ओर मुस्लिम पर्व ईद और मुहर्रम हैं;एक ओर क्रिसमस और गुड फ्राइडे हैं तो दूसरी ओर गुरु नानक जयंती और बुद्ध पूर्णिमा। इन सभी त्योहारों का एक साथ मनाया जाना और समाज के हर वर्ग का इसमें शामिल होना ही भारत को विशिष्ट बनाता है। शिक्षक दिवस और ईद-ए-मिलाद का संगम इसी बहुसांस्कृतिक परंपरा की पुष्टि करता है जो अच्छी बात है।

साथियों बात अगर हम वैश्विक शांति और शिक्षा का सेतु व भारतीय लोकतंत्र का संदेश की करें तो,आज कीदुनियाँ में जहाँ हिंसा, युद्ध और आतंकवाद जैसी चुनौतियाँ हैं,वहाँ शिक्षा और धार्मिक मूल्यों का सही संगम ही मानवता को बचा सकता है।शिक्षक दिवस शिक्षा के महत्व को उजागर करता है,जबकि ईद- ए- मिलाद हमें धार्मिक और नैतिक मूल्यों की याद दिलाता है। यदि इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो यह मानव सभ्यता के लिए एक मजबूत सेतु का काम करता है।भारत का संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। यहाँ न तो किसी एक धर्म को सर्वोपरि माना गया है और न ही किसी आस्था के अनुयायियों कोकमतर आँका गया है। 5 सितंबर 2025 का यह संयोग भारतीय लोकतंत्र के उस मूलभूत सिद्धांत को और मज़बूत करता है,जिसमें सभी धर्म और मान्यताएँ समान रूप से आदरणीय हैं। यह दुनिया को यह संदेश देता है किलोकतंत्र केवल चुनाव या शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह विविधताओं को साथ लेकर चलने की क्षमता भी है।दोनों पर्वों के संगम से समाज में सामूहिक उत्साह का वातावरण बनेगा। विद्यालयों और मस्जिदों से निकलने वाले संदेश मिलकर समाज में भाईचारे और शांति को और गहरा करेंगे। यह अवसर केवल धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि 5 सितंबर 2025 को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस और ईद-ए-मिलाद का संगम भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र की जीवंत मिसाल है।यह केवल तिथियों का मेल नहीं, बल्कि शिक्षा और धर्म के साझा मूल्यों का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम किसी भी समुदाय से आते हों, हमारे लक्ष्य और मूल्य समान हैंज्ञान, नैतिकता, इंसानियत और समाज का कल्याण। यह अद्वितीय अवसर भारत की उस आत्मा को प्रकट करता है, जो सदैव विविधताओं में एकता और विभिन्नताओं में सामंजस्य का मार्ग दिखाती है।

देश के पहले उन्नत चालक सहायता प्रणाली सेफ्टी फीचर वाले स्कूटर ओला एस1 प्रो स्पोर्ट में क्या हैं पांच खासियत

ओला एस1 प्रो स्पोर्ट भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को लगातार बेहतर किया जा रहा है। इसी क्रम में देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन निर्माता ओला इलेक्ट्रिक की ओर से 15 अगस्त को ADAS सेफ्टी फीचर के साथ ओला एस1 प्रो स्पोर्ट स्कूटर लॉन्च किया गया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या पांच खासियत दी गई हैं। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। जिसे देखते हुए कई वाहन निर्माताओं की ओर से नए उत्पादों को पेश और लॉन्च किया जा रहा है। वहीं कुछ निर्माता अपने मौजूदा पोर्टफोलियो को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक की ओर से भी ऑफर किए जाने वाले ओला एस1 प्रो के स्पोर्ट वर्जन को 15 अगस्त को लॉन्च किया है। इस स्कूटर को किस तरह की खासियत के साथ ऑफर किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

OLA S1 Pro Sport स्कूटर लॉन्च हुआ

ओला इलेक्ट्रिक की ओर से 15 अगस्त को ही अपने नए स्कूटर ओला एस1 प्रो स्पोर्ट स्कूटर को भारत में लॉन्च किया है। निर्माता की ओर से इस स्कूटर को अभी सिर्फ लॉन्च ही किया है, लेकिन इसकी डिलीवरी को कुछ समय बाद शुरू किया जाएगा।

क्या हैं पांच खासियत

ओला के नए एस1 प्रो स्पोर्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर में निर्माता की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है।

निर्माता की ओर से इसे काफी स्पोर्टी डिजाइन के साथ पेश किया गया है। इसमें स्ट्रीट स्टाइल की फेयरिंग का उपयोग किया गया है।

इसके साथ ही इसमें कार्बन फाइबर का उपयोग किया गया है। जिससे यह स्कूटर वजन में कम हो जाता है।

इसमें ADAS जैसे सेफ्टी फीचर को भी दिया गया है। जिससे यह देश का पहला ऐसा स्कूटर बन गया है जिसमें ADAS जैसे सेफ्टी फीचर को दिया गया है।

इसके अलावा इसमें 5.2 kWh की क्षमता का बैटरी पैक दिया गया है जिसे फुल चार्ज के बाद 320 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

इसे भारत में 1.50 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। लेकिन इसकी डिलीवरी को जनवरी 2026 में शुरू किया जाएगा। फिलहाल इस स्कूटर को 999 रुपये में रिजर्व करवाया जा सकता है।

बाइक का इंजन ऑयल कब बदलें? अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है भारी नुकसान, जानें पूरी डिटेल

परिवहन विशेष न्यूज

बाइक इंजन ऑयल भारत में बड़ी संख्या में लोग रोज के कामों को पूरा करने के लिए बाइक का उपयोग करते हैं। बाइक का इंजन सही तरह से काम करता रहे इसके लिए इंजन ऑयल काफी जरूरी होता है। अगर इंजन ऑयल खराब या कम हो जाए तो गंभीर नुकसान भी हो सकता है। इससे बचने के लिए कब इंजन ऑयल को बदलना चाहिए। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश में लोग रोज के कामों को पूरा करने के लिए बाइक का उपयोग करते हैं। कई लोग बाइक का अच्छी तरह ध्यान रखते हैं तो कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं। लापरवाही बरतने पर इंजन को भी नुकसान होता है। कई बार लोग इंजन ऑयल को बिना बदले और चेक किए भी चलाते हैं। लेकिन ऐसा करना कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। इंजन ऑयल को कब बदलना (bike engine oil change) बेहतर रहता है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

लापरवाही से नुकसान

किसी भी बाइक में इंजन उसका सबसे जरूरी हिस्सा होता है। इंजन के लिए सबसे जरूरी इंजन ऑयल होता है। कई बार लोग इंजन और इंजन ऑयल को लेकर लापरवाही बरतते हैं। जिससे बाद में उनको भारी नुकसान हो जाता है।

मैनुअल बुक पढ़ना जरूरी

निर्माता की ओर से अपनी हर बाइक के साथ मैनुअल बुक या ई-मैनुअल बुक दी जाती है। बाइक की मैनुअल में हर बात की जानकारी के साथ ही यह भी जानकारी होती है कि किस बाइक में किस तरह के इंजन ऑयल का उपयोग करना चाहिए। साथ में यह भी जानकारी दी जाती है कि इंजन ऑयल को कब बदलना चाहिए। इसे पढ़कर आप इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि इंजन ऑयल को कब बदलना सही होगा।

इंजन से आवाज

अगर आपकी बाइक को चलाते हुए इंजन से सामान्य से ज्यादा आवाज आने लगती है, तो ऐसी स्थिति में इंजन ऑयल को बदलना काफी जरूरी हो जाता है। जब भी बाइक में नया इंजन ऑयल डाला जाता है तो इंजन की आवाज काफी कम हो जाती है, लेकिन जब भी ऑयल खराब हो जाता है तो इंजन से आने वाली आवाज बढ़ने लगती है।

ओवरहीट होने पर भी चेक करें

अगर आपकी बाइक चलते हुए काफी तेजी से ओवरहीट होने लगती है, तो भी इस बात की संभावना होती है कि इंजन ऑयल खराब हो गया हो। इसके साथ ही यह भी खतरा होता है कि इंजन में ऑयल का स्तर काफी कम हो गया हो। ऐसा होने पर इंजन को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे संकेत मिलने पर इंजन ऑयल को चेक कर उसे बदल देना चाहिए।

टाटा सफारी, इनोवा, स्कॉर्पियो नहीं, बल्कि इस सस्ती 7-सीटर कार ने जुलाई में किया कमाल, टॉप-5 में शामिल हुई कौन सी कारें

सबसे ज़्यादा बिकने वाली 7 सीटर कारें भारत में हर महीने लाखों की संख्या में वाहनों की बिक्री की जाती है। जिनमें सात सीटों वाली कई कारों का भी योगदान होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई महीने में कौन सी सात सीटों वाली कारों की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। Top-5 लिस्ट में कौन सी कारों को शामिल किया गया है। आइए जानते हैं।

नईदिल्ली। भारत में हर महीने बड़ी संख्या में कारों की बिक्री की जाती है। कई सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली कारों में सात सीटों वाली कारों की भी मांग रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान देशभर में कौन सी सात सीटों वाली कारों की सबसे ज्यादा मांग रही है। Top-5 लिस्ट में कौन सी कारों को शामिल किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Suzuki Ertiga

मारुति सुजुकी की ओर से सात सीटों वाली कार के तौर पर मारुति अर्टिगा की बिक्री की जाती है। लंबे समय से इस गाड़ी की बाजार में काफी मांग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान भी इसे सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। जानकारी के मुताबिक बीते महीने के दौरान इस एमपीवी की 16604 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जबकि इसके पहले 2024 में यह संख्या 15701 यूनिट्स की थी।

Mahindra Scorpio

महिंद्रा की ओर से भी स्कॉर्पियो को बाजार में सात सीटों के विकल्प के साथ ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान इस गाड़ी की 13747 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जबकि 2024 में इसी अवधि में इसकी 12237 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। महिंद्रा की ओर से स्कॉर्पियो ब्रॉन्ड के तहत क्लासिक और स्कॉर्पियो एन की बिक्री देशभर में की जाती है।

Toyota Innova

टोयोटा की ओर से इनोवा को भी सात सीटों के साथ ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी की बीते महीने के दौरान 9119 यूनिट्स की बिक्री देशभर में हुई है। जबकि 2024 में यह संख्या 9912 यूनिट्स की थी। आंकड़ों के मुताबिक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी बिक्री में आठ फीसदी की कमी दर्ज की गई है।

Kia Carens

किआ की ओर से भी कैरेंस को सात सीटों के विकल्प में ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस एमपीवी की बीते महीने के दौरान 7602 यूनिट्स की बिक्री की गई है। 2024 में इसी अवधि के दौरान इसकी 5679 यूनिट्स की बिक्री की गई है। निर्माता ने इसी साल इसके क्लाविस वर्जन को बाजार में लॉन्च किया है।

Mahindra Bolero

महिंद्रा की ओर से बोलेरो को भी सात सीटों के विकल्प के साथ बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान इस गाड़ी की 7513 यूनिट्स की बिक्री देशभर में हुई है। जबकि 2024 में यह संख्या 6930 यूनिट्स की थी।

एमजी विंडसर ईवी के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की अग्रिम भुगतान के बाद जाएगी कितनी ईएमआई

कार वित्त योजना एमजी मोटर्स भारत में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री करती है। निर्माता की ओर से MG Windsor EV की भी बिक्री की जाती है। इस ईवी के बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। ब्रिटिश वाहन निर्माता MG मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली MG Windsor EV को भी बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

MG Windsor EV Price

एमजी मोटर्स की ओर से Windsor EV के बेस वेरिएंट को 13.99 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसे दिल्ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 14.94 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 13.99 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के अलावा करीब 6300 रुपये आरटीओ और इंश्योरेंस के करीब 73 हजार रुपये देने होंगे। इसके अलावा इसके लिए टीसीएस चार्ज के 14700 रुपये देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 14.94 लाख रुपये हो जाती है।

दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

अगर इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 12.94 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 12.94 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 20820 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी कार

अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 12.94 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 20820 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप MG Windsor EV के लिए करीब 4.55 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 19.49 लाख रुपये देंगे।

किनसे होगा मुकाबला

JSW MG की ओर से Windsor EV को इलेक्ट्रिक गाड़ी के तौर पर लाया जाता है। बाजार में इसे कई एसयूवी से चुनौती मिलती है, लेकिन इसका सीधा मुकाबला Tata Curvv EV, Mahindra BE6 जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ होता है।

विनफास्ट लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक एमपीवी आ सकती है भारत, कैसे हैं फीचर्स और कितनी होगी रेंज

विनफास्ट लिमो ग्रीन वियतनाम की वाहन निर्माता विनफास्ट की ओर से भारत में जल्द ही अपनी कारों को लॉन्च किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से VF6 और VF7 के अलावा एक और गाड़ी को लाने की तैयारी की जा रही है। इसे किस सेगमेंट में लाया जाएगा। किस तरह के फीचर्स और रेंज के साथ इसे लॉन्च किया जाएगा। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। जिसे देखते हुए कई निर्माता भारत में अपनी कारों को पेश और लॉन्च कर रहे हैं। वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता विनफास्ट भी जल्द ही अपनी दो एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके अलावा निर्माता और किस गाड़ी को भारत में लॉन्च कर सकती है। इसमें कैसे फीचर्स और रेंज को ऑफर किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Vinfast लाएगी तीसरी गाड़ी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनफास्ट की ओर से भारत में तीसरी गाड़ी को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से इस गाड़ी के लिए पेटेंट को भारत में फाइल कर दिया गया है।

किस गाड़ी को करेगी लॉन्च

जानकारी के मुताबिक निर्माता की ओर से Vinfast Limo Green इलेक्ट्रिक एमपीवी को भारत में लॉन्च किया जा सकता है। इस इलेक्ट्रिक एमपीवी को कमर्शियल वाहन के तौर पर देश में लॉन्च किया जा सकता है।

कैसे होंगे फीचर्स

निर्माता की ओर से लीमो ग्रीन इलेक्ट्रिक एमपीवी को सात सीटों वाली इलेक्ट्रिक एमपीवी के तौर पर लाया जाएगा। इसमें एलईडी डीआरएल, एलईडी लाइट्स, 18 इंच अलॉय व्हील्स, 170 एमएम ग्राउंड क्लियरेंस, 10.1 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, चार स्पीकर, सिंगल जोन एसी, एयरबैग, एबीएस, ईबीडी जैसे कुछ फीचर्स को शामिल किया जाएगा। इसका इंटीरियर भी ब्लैक थीम पर हो सकता है।

कितनी होगी रेंज

विनफास्ट की ओर से इस सात सीटों वाली इलेक्ट्रिक एमपीवी में 60.13 kWh की क्षमता की एलएफपी बैटरी को दिया जाएगा। जिसे सिंगल चार्ज में 450 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। यह डीसी फास्ट चार्जर से 10 से 70 फीसदी तक सिर्फ 30 मिनट में चार्ज हो जाएगी। इस एमपीवी में ड्राइविंग के लिए ईको, कम्फर्ट और स्पोर्ट्स मोड को दिया जाएगा।

किनसे होगा मुकाबला

विनफास्ट की ओर से लीमो ग्रीन इलेक्ट्रिक एमपीवी को भारत में कमर्शियल वाहन सेगमेंट में ऑफर किया जा सकता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला BYD eMax के साथ होगा।

कब होगी लॉन्च

विनफास्ट की ओर से अभी इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस सात सीटों वाली इलेक्ट्रिक एमपीवी को भारत में 2026 तक लॉन्च किया जा सकता है।

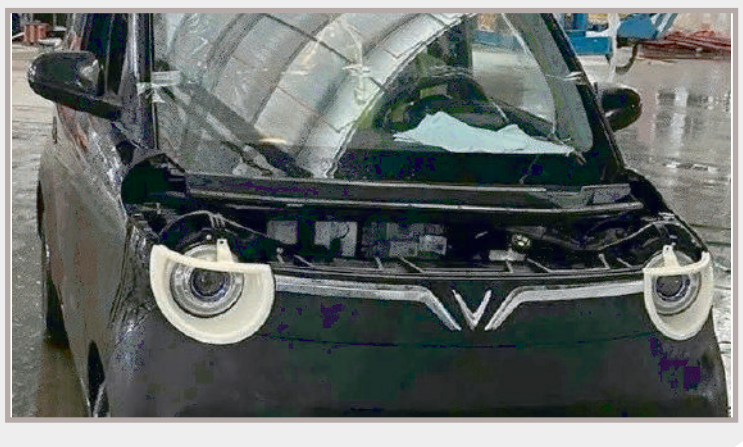

बच्चों, किशोरों में बढ़ती स्क्रीन टाइम की समस्या से पूरा विश्व परेशान है

विजय गर्ग

उन्नीस साल का एक लड़का बारह–बारह घंटे मोबाइल गेम खेलता था। साल भर तक वह ऐसा ही करता रहा। उसने किसी से बातचीत करना, बाहर जाना , लोगों से मिलना , जुलना सब कुछ छोड़ दिया था। हर वक्त बैठे रहने से उसकी रीढ़ की हड्डी में समस्या हो गई। दूसरी समस्याएं भी आ गईं।

स्वीडन ने स्कूलों में स्क्रीन को बैन कर दिया। अब वहां किताबों की वापसी हो रही है। बच्चे सिर्फ किताबों से ही पढ़ेंगे। स्वीडन ने सुधारा, बाकी देश कब सुधारेंगे, वक्त बताएगा। अपने देश में तो अधिकांश दल अपने-अपने घोषणा पत्रों में बच्चों को लैपटाप और मोबाइल देने की बातें करते हैं।

नौ साल के एक बच्चे की अचानक भूख कम हो गई। उसने खेलना छोड़ दिया। स्कूल का होमवर्क बंद कर दिया। रात भर सोता भी नहीं था। बस मोबाइल देखता रहता , स्कूल भी नहीं जाना चाहता था। उसके नम्बर भी बहुत कम आ रहे थे। जब माता-पिता ने डाक्टर से सलाह ली और डाक्टर ने उसका स्क्रीन टाइम कम करने को कहा तो माता-पिता ने उससे मोबाइल ले लिया। बच्चे को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि चाकू से उसने अपने हाथ की नस काट डाली। जब उसे अस्पताल में दाखिल कराया तो उसमें गहरे अवसाद के लक्षण भी पाए गए। यह अवसाद स्क्रीन पर अधिक समय बिताने के कारण हुआ था। इलाज से धीरे-धीरे उसका मूड ठीक हुआ। नींद आने लगी। अपने स्कूल के कामों में भी मन लगाने लगा।

ऐसे ही एक दूसरे मामले में पंद्रह साल की एक बच्ची जो हमेशा अपनी कक्षा में टॉप करती थी, लेकिन धीरे-धीरे उसने पढ़ना-लिखना, दोस्तों से मिलना सब छोड़ दिया। रात में तीन, चार बजे तक वीडियो देखती रहती। उसे लगातार स्क्रीन देखने के कारण गम्भीर अनिद्रा रोग हो गया था।

इसी तरह तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला एक बच्चा छोटी-छोटी बात पर गुस्से से भर जाता। चीजों को तोड़ने-फोड़ने लगता। गालियां देने लगता। उसे भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां तक कि उसका स्कूल भी बदलना पड़ा। डाक्टरों ने जब इलाज के दौरान माता-पिता से बातचीत की तो पता चला कि मां हर समय वीडियो और रील्स बनाने में व्यस्त रहती थी।

उन्नीस साल का एक लड़का बारह-बारह घंटे मोबाइल गेम खेलता था। साल भर तक वह ऐसा ही करता रहा। उसने किसी से बातचीत करना, बाहर जाना , लोगों से मिलना , जुलना सब कुछ छोड़ दिया था। हर वक्त बैठे रहने से उसकी रीढ़ की हड्डी में समस्या हो गई। दूसरी समस्याएं भी आ गईं। जैसे कि वह जहां, तहां मूत्र विसर्जित कर देता। जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, वह ठीक से चल भी नहीं सकता था। उसकी रीढ़ की हड्डी का मुश्किल भरा आपरेशन करना पड़ा।

ये सारे आंकड़े महानगर के हैं, कल्पना कीजिए कि हमारे देश के दूर-दराज के इलाकों में क्या होता होगा, क्योंकि गांवों में भी मोबाइल पर समय बिताने का एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। वहां तो महानगरों जैसी चिकित्सा सुविधाएं भी मौजूद नहीं हैं। इस लेखिका ने कुछ साल पहले अपने गांव में देखा था कि वहां लोग अपने आसपास वालों से भी बातें नहीं करते। वे गांव जहां चौपाल संस्कृति थी, लोग एक-दूसरे से मिलते, जुलते थे, बातचीत करते थे, सुख-दुःख पूछते थे, वह संस्कृति गायब हो गई है। पहले इसका बड़ा हिस्सा टीवी ने गायब किया और अब मोबाइल ने तो जैसे सर्वनाश ही कर दिया।

बच्चों, किशोरों में बढ़ती स्क्रीन टाइम की समस्या से पूरा विश्व परेशान है। आस्ट्रेलिया ने तो सोलह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल रखना भी बैन कर दिया है। बहुत से दूसरे देश भी ऐसा ही करने की सोच रहे हैं। स्वीडन में डेढ़ दशक पहले किताबों को स्कूलों से बिल्कुल गायब कर दिया था। छोटी से छोटी कक्षा का बच्चा स्क्रीन से ही पढ़ रहा था। लेकिन वहां पाया गया कि इससे बच्चों में नया कुछ सीखने की क्षमता घट रही थी। वे आंखों से लेकर शरीर के अन्य तमाम अंगों के रोगों के शिकार भी हो रहे थे। उनका गुस्सा बढ़ रहा था। वे हिंसक हो रहे थे। अंततः स्वीडन ने स्कूलों में स्क्रीन को बैन कर दिया। अब वहां किताबों की वापसी हो रही है। बच्चे सिर्फ किताबों से ही पढ़ेंगे। स्वीडन ने सुधारा , बाकी देश कब सुधारेंगे, वक्त बताएगा। अपने देश में तो हाल यह है कि अधिकांश दल अपने-अपने घोषणा पत्रों में बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल देने की बातें करते हैं। कभी चुनाव हारने–जीतने के मुकाबले दलों को बच्चों और देश के भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए। हद तो ये है कि माता-पिता अपने शिशुओं के हाथों में मोबाइल पकड़ा देते हैं और बहुत गौरव से वीडियो और रील बनाते है। बताते हैं कि उनका तो इतना छोटा बच्चा ही

मोबाइल चलाना जानता है।

ऊपर जिन केसेज का जिक्र किया गया है, वे मनोवैज्ञानिक और डाक्टरों द्वारा ही बताए गए हैं। कुछ माह पहले अपने एक परिचित मनोवैज्ञानिक से मिलने गई थी। उनका क्लीनिक दक्षिण दिल्ली के एक बहुत पाश इलाके में है। वहां बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। ये मित्र कुछ उम्र दराज हैं। एक दूसरे डाक्टर बहुत युवा हैं। उनके पास बहुत छोटे बच्चे भी आते हैं। जब रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या यहां बहुत छोटे बच्चे भी आते हैं। तो उन्होंने कहा कि हां आठ साल तक के बच्चे आते हैं। कितने पूछने पर कहा कि खूब आते हैं। यह संख्या बढ़ती ही जा रही है।

चिकित्सकों का यह भी मानना है कि ऐसे बच्चों में आत्महत्या के विचार भी तेजी से आते हैं। इसलिए इनके बदले व्यवहार से सावधान रहना चाहिए। चिकित्सकों से भी जरूरी सलाह लेनी चाहिए। बच्चों को डिजिटली परेशान भी किया जाता है। कई बच्चों ने स्कूलों में अपनी कहानी बताई भी थी। बहुत से स्कूल मोबाइल फोन्स पर रोक लगा चुके हैं मगर इससे भी समस्या सुलझती नहीं है क्योंकि स्कूल घरों की निगरानी तो कर नहीं सकते कि बच्चे वहां क्या कर रहे हैं। यह काम तो माता-पिता तथा अन्य परिजनों का है।

इसी साल फरवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूलों में मोबाइल फोन को बैन नहीं किया जा सकता। हां स्कूलों को यह प्रविधि विकसित करनी चाहिए कि वे बच्चों को बताएं कि वे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसे कितना समय दें जिससे कि उनकी अन्य गतिविधियों पर कोई असर न पड़े। स्कूल उन्हें सुरक्षित तरीके से अपने पास रखें और लौटा दें। मोबाइल को सिर्फ भोजन की छुट्टी आदि में ही इस्तेमाल करें। बच्चों को इसके फायदे, नुकसान बताने के लिए काउंसलिंग भी की जा सकती है। इस आदेश को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए आदेश जारी किया था कि वे स्मार्टफोन के उपयोग की पॉलिसी बनाएं। इसीलिए कई स्कूल अब सिर्फ नम्बर वाले फोन के उपयोग की सहमति दे रहे हैं। जिससे कि किसी आपात स्थिति में उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस दौर में बच्चों के हाथ में मोबाइल चुनौतियां और अधिक बढ़ा सकता है। इसके अलावा सिर्फ सरकारी स्कूल ही क्यों, निजी स्कूलों में भी बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। उनकी सुरक्षा भी जरूरी है।

बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम किया जाए, इसके लिए माता-पिता को प्रशिक्षण देना भी शुरू किया गया है। डिजिटल समय पर लगभग कर्फ्यू लगाने की बात बताई जाती है। व्यवहार संबंधी परिवर्तनों से कैसे निपटें यह बताया जाता है। बच्चे क्या देख रहे हैं, माता-पिता इस पर भी ध्यान दें। लेकिन इन दिनों महानगरों में जब अधिकांश माता-पिता नौकरी पर चले जाते हैं, तब यह निगरानी करना बहुत मुश्किल भी है।

जब बच्चों को इन बातों को ध्यान में रखते हुए हैंडल किया गया तो परिणाम सकारात्मक निकले।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

आत्महत्या रोकथाम दिवसः जागरूकता बढ़ाना

विजय गर्ग

हर 45 सेकंड में, कोई दुखद रूप से अपना जीवन लेता है, जिसके परिणामस्वरूप हर साल दुनिया भर में लगभग 703,000 आत्महत्याएं होती हैं। आत्महत्या का प्रभाव व्यक्ति से बहुत आगे तक पहुंचता है, दुःख के मद्देनजर छोड़ देता है और अनगिनत अन्य लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। यह जरूरी है कि हम न केवल आत्महत्या बल्कि अंतर्निहित मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को भी संबोधित करें जो इन दुखद परिणामों में योगदान करते हैं।

इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस , आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक पहल के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को, इसका उद्देश्य कलंक को कम करना, संगठनों और सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह एकजुट प्रयास एक शक्तिशाली संदेश भेजता हैः आत्मघाती मौत न केवल एक व्यक्तिगत मामला है, बल्कि दूरगामी परिणामों के साथ एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है।

एक्शन के माध्यम से आशा पैदा करना

यह विषय एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमेशा आत्महत्या का विकल्प होता है। यह हमें आशा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह पहचानने के लिए प्रेरित करता है कि सुरंग के अंत में प्रकाश है। मदद लेने और एक दूसरे का समर्थन करने से, हम उन चुनौतियों को दूर कर सकते हैं जो आत्महत्या के विचारों में योगदान करती हैं।

उद्देश्य

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस न केवल आत्महत्या को रोकने बल्कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है। मुख्य उद्देश्यों में हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, व्यक्तियों को निवारक कार्रवाई के माध्यम से आत्म-हानि और आत्महत्या को संबोधित करने का अधिकार देना और घरों, स्कूलों और कार्यस्थलों सहित विभिन्न सेटिंग्स में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुली चर्चाओं को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अन्य प्रासंगिक अभिनेताओं की क्षमता का निर्माण करना, सामान्य आबादी और जोखिम वाले समूहों को सकारात्मक और सूचनात्मक संदेश देना और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों ने आत्महत्या का अनुभव किया है या विचार कर रहे हैं, उन्हें अपनी कहानियों को साझा करने और पेशेवर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

जानिए अगर आपको खतरा है

नौकरी या वित्तीय नुकसान हुआ ऐसी स्थिति में हैं या हैं जो आघात या दुर्व्यवहार का उत्पादन करती हैं अनुभवी मानसिक और / या पदार्थ उपयोग विकार सीमित पहुंच है या स्वास्थ्य देखभाल तक कोई पहुंच नहीं है यदि आप या कोई प्रियजन अपना जीवन लेने या आत्म-हानि के बारे में विचार करने के बारे में सोच रहा है, तो कृपया परामर्श की तलाश करें। आइए हम जीवन बचाने की अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट रहें। जागरूकता बढ़ाने, कलंक को कम करने और सहायक वातावरण को बढ़ावा देने से, हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है और व्यक्ति मदद लेने के लिए सशक्त महसूस करते हैं। याद रखें, हमेशा आशा होती है, और एक साथ कार्रवाई करके, हम जीवन को बचा सकते हैं, एक समय में एक व्यक्ति।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

कैसे कल की टेक्नोलॉजीज युद्धस्थान बदल रहे हैं

विजय गर्ग

कल की प्रौद्योगिकियां मौलिक रूप से युद्ध के मैदान को फिर से आकार दे रही हैं, पारंपरिक युद्ध से परे जा रही हैं और नए डोमेन और संघर्ष के तरीकों को पेश कर रही हैं। इन उन्नत तकनीकों का एकीकरण न केवल रणनीति बदल रहा है, बल्कि सैन्य सिद्धांत, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पुनर्मूल्यांकन के लिए भी मजबूर कर रहा है। यहां कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकियां दी गई हैं जो युद्ध की जगह बदल रही हैं: 1.। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और स्वायत्तप्रणाली:

संवर्धित निर्णय लेना: ऐआई वास्तविक समय में विभिन्न स्रोतों (उपग्रहों, ड्रोन, सेंसर) से भारी मात्रा में डेटा की प्रक्रिया और विश्लेषण कर सकता है, कमांडरों को स्थितिजन्य जागरूकता और निर्णय लेने की गति के साथ प्रदान कर सकता है जो पहले असंभव था।

स्वायत्त हथियार: यह सबसे महत्वपूर्ण और नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण घटनाओं में से एक है। घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली मानव हस्तक्षेप के बिना लक्ष्यों की पहचान, ट्रैक और संलग्न कर सकती है। जबकि वे मानव जोखिम को कम करने और गति बढ़ाने की क्षमता प्रदान करते हैं, वे जवाबदेही, घातक बल के उपयोग पर मानव नियंत्रण के नुकसान और हथियारों की एक नई तरह की दौड़ की क्षमता के बारे में गंभीर सवाल भी उठाते हैं।

स्वरमिंग: ड्रोन और अन्य मानवरहित प्रणालियों के एआई-सक्षम झुंड सरासर संख्याओं के साथ एक विरोधी की सुरक्षा को

अभिभूत कर सकते हैं, उनके कार्यों का समन्वय कर सकते हैं और वास्तविक समय में अपनी रणनीति को अनुकूलित कर सकते हैं।2. । मानव रहित और रोबोट सिस्टम:

ड्रोन (यूएवी): पहले से ही आधुनिक संघर्ष का एक प्रमुख, ड्रोन निगरानी, टोही और सटीक हमलों के लिए बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं।

मानव रहित ग्राउंड वाहन (यूजीवी) और मानव रहित मरीन सिस्टम (यूएमएस): इन प्लेटफार्मों को कई प्रकार के कार्यों के लिए विकसित किया जा रहा है, जो पुनर्आपूर्ति और रसद से लेकर खदान समाशोधन और टोही तक, मानव कर्मियों को खतरनाक वातावरण में नुकसान के रास्ते से बाहर रखते हैं। 3। साइबर और सूचना युद्ध:

संघर्ष का एक नया डोमेन: साइबरस्पेस अब एक केंद्रीय युद्धक्षेत्र है। राज्य और गैर-राज्य अभिनेता गंभीर बुनियादी ढांचे, संचार और वित्तीय प्रणालियों को बाधित करने के लिए साइबर हमले शुरू कर सकते हैं, अक्सर प्रत्यक्ष सैन्य सगाई की आवश्यकता के बिना।

सूचना युद्ध: प्रौद्योगिकियों का उपयोग विघटन फैलाने, जनमत में हेरफेर करने और संघर्ष की कथा को प्रभावित करने, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध के बीच की रेखाओं को धुंधला करने के लिए किया जा रहा है

हाइपरसोनिक हथियार:

बेजोड़ गति और गतिशीलता: हाइपरसोनिक हथियार, जो मच 5 से अधिक की गति से यात्रा करते हैं, वर्तमान मिसाइल रक्षा प्रणालियों के साथ पता लगाने और अवरोधन करने के लिए बेहद मुश्किल हैं। वे एक विरोधी के लिए प्रतिक्रिया समय को कम करके और तेजी से, लंबी दूरी के हमलों को सक्षम करके एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। 5. । क्वांटम टेक्नोलॉजीज:

कम्प्यूटिंग और सेंसिंग में सफलता: विकास में अभी भी, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग में सैन्य क्षमताओं में क्रांति लाने की क्षमता है। क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा एन्क्रिप्शन को तोड़ सकते हैं, जबकि क्वांटम सेंसर पनडुब्बियों और अन्य चोरी के लक्ष्यों के लिए पहचान के अभूतपूर्व स्तर प्रदान कर सकते हैं। 6। निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEWs):

उच्च ऊर्जा लेजर और माइक्रोवेव: ये हथियार लक्ष्य को अक्षम या नष्ट करने के लिए केंद्रित विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वे पारंपरिक मुनियों के लिए एक सटीक, लागत प्रभावी और अक्सर गैर-घातक विकल्प प्रदान करते हैं, जिसमें मिसाइल रक्षा से लेकर दुश्मन ड्रोन को अक्षम करने तक के अनुप्रयोग होते हैं। 7. । इमर्सिव टेक्नोलॉजीज (एआर/वीआर):

प्रशिक्षण और सिमुलेशन: संवर्धित वास्तविकता (एआर) और आभासी वास्तविकता (वीआर) सैन्य प्रशिक्षण को बदल रहे हैं, जिससे सैनिकों को एक सुरक्षित, नियंत्रित वातावरण में विभिन्न लड़ाकू परिदृश्यों का अभ्यास और जवाब देने की अनुमति मिलती है।

स्थितिजन्य जागरूकता: एआर वास्तविक समय की बुद्धिमत्ता के ओवरले के साथ जमीन पर सैनिकों को प्रदान कर सकता है, जैसे कि दुश्मन की स्थिति या टुकड़ी की चाल, सीधे उनके दृष्टिकोण के क्षेत्र पर। ये प्रौद्योगिकियां केवल पृथक प्रगति नहीं हैं; उनका अभिसरण एक अत्यधिक परस्पर युद्ध का स्थान बना रहा है जहां भौतिक और आभासी डोमेन आपस में जुड़े हुए हैं। यह प्रतिमान बदलाव सैन्य और राजनीतिक नेताओं के लिए जटिल सवाल उठाता है, जिनमें शामिल हैं:

नैतिक और कानूनी ढांचे: इन प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से स्वायत्त हथियारों के विकास और उपयोग के लिए नए अंतरराष्ट्रीय कानूनी और नैतिक दिशानिर्देशों की आवश्यकता होती है।

असममित युद्ध: उन्नत प्रौद्योगिकियां प्रमुख सैन्य शक्तियों तक सीमित नहीं हैं।

शिक्षा व्यवस्था और संस्थाओं संस्थाओं के दायित्व

विजय गर्ग

भारत की राजनीति को लेकर संचार माध्यम प्रतिदिन जो परोसते हैं, वह यही दर्शाता है कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति के अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंश भूल गए हैं: सुसंस्कृत सामाजिक व्यवहार और मर्यादापूर्ण वैचारिक अभिव्यक्ति! हमारे तरुण और युवा उन लोगों की तरफ देखते हैं, जिनका कृत्य और व्यवहार उनके समक्ष लगातार आता रहता है। इसमें सबसे पहले आते हैं चयनित प्रतिनिधि, विशेषकर संसद में जो कुछ होता है, या नहीं होता है। सवाल है कि क्या हमारे देश में संसद को सुचारु रूप से चलाने की क्षमता प्राप्त करना शेष है ? अगर ऐसा है, । इस चिंताजनक स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। यह प्रश्न देश भर के शिक्षकों के समक्ष भी एक चुनौती बनकर पिछले कुछ दशकों में उभरा है कि क्या हम ऐसे व्यक्तित्व निर्माण में असफल रहे हैं, जो भारतीय लोकतंत्र को उसके मूलभूत सिद्धांतों और अवधारणाओं के अनुसार चला सकें? भारतीय ज्ञान परंपरा पर हर कोई गर्व करता है और यह कहने में किसी को हिचक नहीं होगी कि भारत ही गणतंत्र को लागू करने में अग्रणी था! मगर वर्तमान स्थिति को देखकर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति निराश ही होगा !

प्रारंभ से 'महाजनो येन गतः सा पन्थाः' का सूत्र बच्चों को सिखाने वाली व्यवस्था इस समय असमंजस का शिकार होकर अपना रास्ता तलाश रही है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का प्रसारण इस असमंजस और अकुलाहट को और बढ़ा देता है। यदि संसद में कामकाज के बजाय हंगामा या अमर्यादित व्यवहार होता है, तो ऐसे दृश्यों को सारा देश बार-बार देखता है। विचारणीय बात यह है कि किशोरों और युवाओं के संवेदनशील मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई किशोर या युवा ऐसा ही व्यवहार अपने शिक्षक के साथ करता है और उस पर पर कार्रवाई की जाती है, तो क्या यह नैसर्गिक न्याय होगा? जनप्रतिनिधियों के पास तो सभी संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, मगर ऐसे किसी किशोर या युवा सामने तो भविष्य का धुंधलका लगातार गहराता जाता है। उनका व्यग्र और व्यथित होना समाज तथा नीति निर्धारकों की समझ में आना चाहिए।

वर्ष 1960 के आसपास लोकतंत्र की प्रारंभिक समझ के लिए तैयार होते युवाओं के सामने उस समय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक वरिष्ट नायक देश में मौजूद थे। उनके त्याग, तपस्या और सेवा इतिहास की गाथाएं बनने के योग्य थीं और ये बनीं भी। आज के युवाओं के समक्ष आदर्श और नैतिकतापूर्ण आचरण वाले वे 'महाजन' कितने हैं और किस स्थिति में हैं, उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है जो हैं, वे समय और व्यवस्था की लगातार बढ़ती चमक-दमक से आच्छादित नई पीढ़ी के आचार-विचार और व्यवहार में छिप जाते हैं, या पीछे धकेल दिए जाते हैं। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नेता भी अपनी राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहते हैं और देश की सियासत की दिशा बदलने में अपनी ऊर्जा लगाते रहने का दिखावा करते रहते हैं। ऐसे नेताओं पर अक्सर कोई रोक-टोक लगाने का कार्य व्यवस्था नहीं कर पाती है। कई बार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग राजनीतिक दलों के दशकों तक तारणहार बने रहते हैं।

कुछ डाक्टर असुविधाजनक अस्पतालों और अध्यापक ग्रामीण स्कूलों में दो-तीन दिन ड्यूटी पर

जाकर जिला स्तर के अधिकारियों से साठगांठ कर हफ्ते भर की पूरी उपस्थिति दर्ज करा लेते हैं। स्कूलों में तो 'एवजी अध्यापक' के चलन की खबरें कई दशकों से आती रही है। निस्संदेह भारत ने अपने युवाओं को प्रखरता और मेधा से वैश्विक पटल पर बड़ा नाम कमाया है, जबकि उसके संभवतः 30-35 फीसद स्कूल ही अपेक्षित

स्तर पर चल रहे हैं, बाकी राम भरोसे हैं। राज्य सरकारें अन्य प्राथमिकताओं में व्यस्त हैं। सरकारी स्कूलों में लगभग दस लाख स्वीकृत पद खाली हैं। व्यवस्था में इस बात को लेकर कोई चिंता दिखाई नहीं देती है। नीति निर्माताओं और उनका क्रियान्वयन करने वालों के लिए तो चमकीले निजी स्कूल उपलब्ध हैं।

शिक्षा की चुनौतियां राष्ट्र के समक्ष उभरने वाली चुनौतियों से अलग नहीं हो सकती हैं। । यह प्रजातंत्र की किस अवधारणा को पोषित करता है कि एक सार्वभौमिक राष्ट्र भारत के लिए किस देश से क्या खरीदा जाए, यह अमेरिका तय करे? यानी वैश्विक स्तर पर जमींदारी जिसे उपनिवेशवाद के आकाओं ने । ईश्वर-प्रदत्त 'उत्तरदायित्व' मान लिया था और खुद द को सुसज्जित कर उन्होंने 'असभ्यों के उद्धार' का उत्तरदायित्व उठा लिया था, वह 'अधिकार' अभी भी उनकी सोच बाहर नहीं हो पाया है। 'अन्य पर श्रेष्ठता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार' की अदम्य अभिलाषा को कुछ लोग छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश अपने बनाए हथियारों को यूक्रेन को बेचते या देते रहें, उस देश के लड़ते रहने में अपनी स्वार्थ पूर्ति करते रहें और भारत पर आरोप लगाएं कि उसके द्वारा रूस से तेल खरीद की वजह से युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है ! ऐसे में राष्ट्रीय एकता का सशक्त होना और विश्व के समक्ष जाहिर होना, देश के सम्मान के लिए आवश्यक है।

भारतीय संस्कृति और संस्कारों पर देश गर्व करता है, पुनः 'विश्व गुरु' बनने के सपने देखता है, लेकिन आज भी अनेक स्थानों पर कुछ लोग दलित दूल्हे का विवाह के अवसर पर घोड़ी पर बैठना सहन नहीं कर पाते हैं। सोच चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हो या गांव के इस (पूर्व) जमींदार की, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह वैचारिकता अब राजनीतिक परिवारों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्वरूप ले रही है। यदि थोड़ी देर के लिए पक्ष-विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह समय किसी भी भारतीय से केवल एक ही अपेक्षा करता है कि वह भारत सरकार की अमेरिका के समक्ष न झुकने की नीति का दृढ़तापूर्वक समर्थन करे, चाहे वह सरकार से कितना ही असंतुष्ट क्यों न हो।

पाकिस्तान के विरुद्ध जब सैन्य कार्रवाई हुई, सारे देश ने एकसाथ उस पर संतोष प्रकट किया, सेना के साहस और तैयारी की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। मगर, इस राष्ट्रीय अभिव्यक्ति में भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, वे ऐसे प्रश्न उठाते रहे, जो सरकार ही नहीं, बल्कि सेना पर भी अविश्वास पैदा कर दें। शायद वे भूल गए कि उन्होंने इस व्यवहार से अपने प्रति जन समाज में अनावश्यक दूरियां बना लीं ! देश में अनुभवी, विचारशील और संयमित नेतृत्व की आवश्यकता हर स्तर पर होती है, राजनीति में इसकी हर दल को सख्त जरूरत होती है। इस परिप्रेक्ष्य में जब भारत में राजनीतिक अपरिपक्वता की स्थिति पर नजर डाली जाए, तो अनगिनत लोगों को अत्यंत निराशा होगी। इन सब मसलों का समाधान तो शिक्षा संस्थानों और संवैधानिक संस्थाओं से ही निकलेगा। जब हमारे भीतर संस्कार, सद्भाव, सदाचार, राष्ट्र प्रेम और कर्त्तव्य परायणता की नींव ही कमजोर होगी, तो जाहिर है कि हमारा व्यक्तित्व भी वैसा ही आकार लेगा । इसलिए शिक्षा व्यवस्था में समय के साथ जरूरत के हिसाब से सुधार कर उसके मूल्यों को समझने और समझाने की आवश्यकता है।

ग्रामीणों ने ओएसआरटीसी बस को बंधक बनाया: मांग की हमें बस दो, फिर बस ले जाओ

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर : ग्रामीणों ने सुंदरगढ़ जिले के बणई थाना अंतर्गत गोबिंदपुर पंचायत कार्यालय परिसर में एक ओएसआरटीसी (मुख्यमंत्री बस सेवा) बस को जब्त कर लिया है। लंबे समय से गोबिंदपुर पंचायत के निवासी मांग कर रहे हैं कि तत्कालीन लक्ष्मी बस या आज की मुख्यमंत्री बस उनके गांव तक चले, लेकिन प्रशासन मौन रहा है। इस संबंध में वे जिला मजिस्ट्रेट से लेकर बणई बीडीओ तक मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलने पर 19 तारीख को जब सुंदरगढ़ जिला मजिस्ट्रेट की संयुक्त शिकायत लहुणीपाड़ा में सुनी गई, तो उन्होंने फिर से जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत की और कहा कि अगर प्रशासन मंगलवार 2 अगस्त तक कोई निर्णय नहीं लेता है, तो वे 3 तारीख को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 143 को अवरुद्ध कर देंगे। कल, ओएसआरटीसी बस गोबिंदपुर गई, यहां तक कि पंचायत की महिलाओं ने फूल और चंदन चढ़ाए और उसे गांव तक ले गईं। जब बस पंचायत कार्यालय से वापस लौट रही थी वे बस को गाँव से होकर चलाने की माँग पर अड़े हुए थे। गाँव वाले कह रहे हैं, ₹बस ले लो, मुझे दे दो।₹ इतने लंबे समय से झमेला चल रहा है, फिर भी कोई नहीं, यहाँ तक कि प्रशासन या पुलिस भी नहीं, गाँव तक पहुँचा है। दूसरी ओर, पिछली सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई लक्ष्मी बस योजना का नाम बदल दिया, और यह सेवा उपलब्ध नहीं है। उनका मानना है कि अगर नवीन पटनायक की मानसिकता को कॉपी-पेस्ट किया जाए, तो यह सेवा उपलब्ध हो जाएगी।

जीएसटी पर सियासत या राहत

जीएसटी दरों में कटौती जनता के लिए राहत का संकेत है, लेकिन बार-बार बदलते तर्क सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं।

जीएसटी लागू होने के बाद सरकार ने नौ साल तक ऊँची दरों को ज़रूरी बताते हुए उनके फायदे गिनाए। अब दरें घटाने पर वही तर्क उलटे रूप में दिए जा रहे हैं। नवरात्र से लागू होने वाली टैक्स राहत निश्चित रूप से उपभोक्ताओं और व्यापार जगत के लिए सकारात्मक संदेश है, परंतु नीतियों में यह विरोधाभास जनता के विश्वास को कमजोर करता है। टैक्स नीति को राजनीति या त्योहारों से जोड़ने के बजाय दीर्घकालिक दृष्टि से स्थिर और ब्यायपूर्ण बनाना ज़रूरी है, ताकि ₹एक देश, एक टैक्स₹ की असली भावना सार्थक हो सके।

- डॉ सत्यवान सौरभ

भारतीय कर व्यवस्था में वर्ष 2017 से लागू हुआ जीएसटी यानी "गुड्स एंड सर्विस टैक्स" उस समय एक ऐतिहासिक सुधार माना गया था। इसे "एक देश, एक टैक्स" की संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया गया और जनता को विश्वास दिलाया गया कि इससे कर व्यवस्था सरल होगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और व्यापारियों को सुविधा मिलेगी। शुरुआत में ही सरकार और उसके आर्थिक सलाहकारों ने ऊँचे टैक्स की दरों को जायज़ ठहराते हुए बताया था कि यह राष्ट्रहित में है और दीर्घकाल में इससे राजस्व बढ़ेगा, विकास दर तेज़ होगी तथा राज्यों को भी मज़बूती मिलेगी।

लेकिन बीते नौ वर्षों में जनता ने देखा कि जीएसटी का बोझ केवल आम उपभोक्ताओं पर बढ़ता गया। ज़रूरी सामानों से लेकर रोज़मर्रा की वस्तुओं पर टैक्स दरें ऊँची बनी रहीं। महँगाई लगातार बढ़ती रही और हर घर का बजट बिगड़ता गया। व्यापारी समुदाय ने भी कई बार शिकायत की कि जीएसटी की जटिल व्यवस्था और ऊँचे टैक्स स्लैब ने उनके कारोबार को प्रभावित किया। छोटे और मझोले उद्योगों को तो कई बार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी।

अब अचानक वही सरकार यह कह रही है कि जीएसटी की दरें घटाई जाएंगी और इससे जनता को सीधी राहत मिलेगी। नवरात्र के अवसर पर इस घोषणा को "टैक्स राहत की दिवाली" कहा जा रहा है। निश्चित ही यह कदम आम उपभोक्ता के लिए सुकून भरा संदेश है। जूते, कपड़े, टीवी, डीटीएच जैसी वस्तुओं पर टैक्स घटाना हर परिवार को सीधे प्रभावित करेगा। लोग त्योहारों के समय खरीदारी कर पाएंगे और बाज़ार में चहल-पहल बढ़ेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो तर्क पहले ऊँचे टैक्स के समर्थन में दिए गए थे, वही तर्क आज घटाने के समर्थन में क्यों दिए जा रहे हैं?

यह विरोधाभास केवल टैक्स दरों तक सीमित नहीं है। यह सरकार की आर्थिक नीतियों की सोच पर भी सवाल खड़े करता है। अगर ऊँचे टैक्स ही विकास का आधार थे, तो नौ साल बाद अचानक उन्हें कम करना कैसे विकास के लिए आवश्यक हो गया? और यदि वास्तव में कम टैक्स से बाज़ार और जनता को राहत मिल सकती है, तो इतने वर्षों तक जनता को ऊँचे टैक्स का बोझ क्यों झेलना पड़ा? आम नागरिक इन सवालों का जवाब चाहता है। वह देख रहा है कि टैक्स नीतियाँ कई बार राजनीति और चुनावी रणनीतियों से जुड़कर बदल जाती हैं। त्योहारों के अवसर पर टैक्स कटौती की घोषणा निश्चित रूप से लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन क्या यह दीर्घकालिक समाधान है? कर नीति को समय-समय पर बदलना और हर बार इसे जनता के हित में बताना, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है।

आज जब सरकार कहती है कि टैक्स घटाने से अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलेगी, तो यह बात सही भी है। टैक्स बोझ कम होने पर लोगों की क्रयशक्ति बढ़ती है, उपभोग बढ़ता है और बाज़ार में रौनक आती है। इससे उत्पादन बढ़ता है और रोज़गार सृजन भी होता है। लेकिन फिर वही प्रश्न—तो इतने वर्षों तक टैक्स ऊँचे रखकर किस उद्देश्य को साधा गया? क्या उस दौरान जनता केवल राजस्व संग्रह की मशीन बनकर रह गई?

सच्चाई यह है कि भारत जैसे विकासशील देश में कर नीति केवल राजस्व जुटाने का साधन नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक संतुलन का आधार भी होनी चाहिए। ज़रूरी सामानों और रोज़मर्रा की वस्तुओं पर टैक्स बोझ कम से कम रखा जाना चाहिए ताकि गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिले। जबकि विलासिता की वस्तुओं पर अपेक्षाकृत ऊँचे टैक्स लगाए जा सकते हैं। लेकिन पिछले वर्षों में हमने देखा कि कई बार यह संतुलन बिगड़ गया और आम नागरिक की जेब पर सीधा असर पड़ा।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि टैक्स में राहत से सरकार के राजस्व पर भी असर पड़ता है। जब राजस्व घटता है तो सरकार या तो घाटा बढ़ाती है या फिर कहीं और से वसूली करती है। ऐसे में जनता को राहत वास्तव में कितनी मिलती है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। यदि बिजली, ईंधन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधे या परोक्ष रूप से टैक्स का बोझ बना रहेगा, तो बाकी वस्तुओं पर टैक्स घटाने का असर सीमित ही होगा।

जीएसटी के नाम पर जिस "एक देश, एक टैक्स" का सपना दिखाया गया था, वह आज भी अधूरा है। अलग-अलग वस्तुओं पर अलग-अलग स्लैब, राज्यों की शिकायतें, जटिल रिटर्न फाइलिंग और बार-बार नियमों का बदलना, ये सब मिलकर इसे जटिल बनाते रहे हैं। अब जबकि टैक्स दरों को घटाने का निर्णय लिया गया है, तो ज़रूरत इस बात की है कि इसे केवल त्योहारों तक सीमित राहत न बनाया जाए, बल्कि पूरी व्यवस्था को स्थिर और संतुलित बनाया जाए।

सरकार को चाहिए कि वह टैक्स नीतियों को राजनीति से ऊपर उठाकर, दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टि से तय करे। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि टैक्स वास्तव में राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान है, न कि केवल बोझ। इसके लिए आवश्यक है कि टैक्स से मिलने वाले राजस्व का सही और पारदर्शी उपयोग हो। यदि जनता देखेगी कि उसके द्वारा दिए गए टैक्स का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत संरचना पर हो रहा है, तो वह टैक्स चुकाने में संकोच नहीं करेगी।

आज की टैक्स राहत का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी उठाना ज़रूरी है कि क्या यह केवल तात्कालिक आकर्षण है या फिर एक दीर्घकालिक सुधार की शुरुआत। जीएसटी जैसे बड़े सुधार को राजनीति और चुनावी लाभ से जोड़कर देखने के बजाय इसे जनता और अर्थव्यवस्था के वास्तविक हित में आगे बढ़ाना होगा। तभी वास्तव में "टैक्स राहत की दिवाली" हर नागरिक के जीवन में रोशनी ला सकेगी।

झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस हेतु आठ बने न्यायिक अधिकारी

वर्द्धा पहले तथा दीपक दुसरे स्थान पर , जहां अकेले दीपक कुमार ही झारखंड निवासी

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड,-झारखंड

रांची , झारखंड हाईकोर्ट की ओर से इसी साल 27 अप्रैल को ली गई झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस (जिला जज) की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट बुधवार को जारी कर दिया गया। इसमें आठ न्यायिक अधिकारियों का चयन किया गया है। इनमें वर्द्धा पहले और दीपक कुमार दूसरे स्थान पर रहे। वहीं अन्य सफल अभ्यर्थियों में जे जनानी, आशुतोष कुमार सिंह, सुशील कुमार सिंह, शिव करण, ज्योतिशील और विजय कुमार श्रीवास्तव शामिल हैं। इन आठ में से सिर्फ एक अभ्यर्थी दुमका निवासी दीपक कुमार झारखंड से हैं। सरैयाहाट प्रखंड के दिग्गी गांव निवासी दीपक कुमार अभी दिल्ली में लोक अभियोजक के पद पर कार्यरत हैं। दीपक की शिक्षा गांव से और हाईस्कूल की पढ़ाई देवघर से की। पटना से स्नातक की डिग्री ली और कानून की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की। उन्होंने कहा- मुझे अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा था, लेकिन राज्य में दूसरे स्थान पर आऊंगा, यह सुखद भी एवं आश्चर्य है। उन्होंने कहा कि जो युवा न्यायिक सेवा में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण घटनाओं, कानूनी अधिनियमों ओर कोर्ट के आदेशों पर गहरी नजर रखनी चाहिए। नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने भगवद्गीता का वह श्लोक भी बताया - ₹ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन₹ जिसका अर्थ होता है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। (ज्ञात हो कि यह भगवद् गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक का अंश है) दीपक के पिता अनंत लाल चौधरी दिग्गी पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं।

झारखंड के पलामू जिले में पुलिस एवं उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ , दो जवान शहीद एक धायल

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , झारखंड के पलामू में उग्रवादियों और जवानों के बीच भीषण मुठभेड़ का मामला सामने आया है। इस मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए हैं। शहीद हुए जवानों की पहचान संतान कुमार और सुनील राम के रूप में हुई है। वहीं इस एनकाउंटर में घायल हुए जवान की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई है। घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वो खतरे से बाहर हैं।इस मामले की जानकारी देते हुए डीआईजी नौशाद आलम ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कर्मा पूजा का आयोजन है और इस दौरान प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी के नक्सली दहशत फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। सूचना के आधार पर एसपी के नेतृत्व में पुलिसकर्मी दो दलों में बांटकर सर्च अभियान में निकले थे। इस दौरान हमले में दो जवान शहीद हो गए।इस मामले की जानकारी देते हुए डीआईजी ने कहा कि जैसे ही जवान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे, छिपे नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन मुठभेड़ में दो जवान, संतन कुमार मेहता और सुनील राम शहीद हो गए। रोहित कुमार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों पहले टाइगर मोबाइल में तैनात रह चुके हैं। गोलीबारी में नक्सलियों के भी हताहत होने की संभावना है, लेकिन शव बरामद नहीं हो सका है। पूरी घटना के बाद क्षेत्र की घेराबंदी कर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पलामू एसपी और वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। शहीद जवानों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। इस मुठभेड़ से पूरे जिले में शोक की लहर है। पुलिस अधिकारियों ने शहीदों की बहादुरी को नमन करते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा और जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तीनों जवान पलामू के ही रहने वाले हैं। शहीद जवान संतान कुमार हैदर नगर थाना क्षेत्र के बरेवा गांव निवासी है जबकि सुनील राम हैदर नगर थाना क्षेत्र के परता गांव के रहने वाले हैं। जख्मी रोहित कुमार पड़वा थाना क्षेत्र के चना गांव के रहने वाले हैं। सुनील कुमार अभियान एसपी का बॉडीगार्ड है जबकि संतान कुमार एवं जख्मी रोहित कुमार टीओपी वन का टाइगर पुलिस जवान है।

जीवन और समाज को रोशन करने वाले शिक्षक

शिक्षक केवल एक पेशे का नाम नहीं है, बल्कि शिक्षक अपने आप में एक "परोपकारी संस्था" है। प्राचीन काल से ही शिक्षक को ईश्वर से भी ऊँचा दर्जा दिया गया है। मानव जीवन के विकास, प्रगति और उत्कृष्टता के लिए शिक्षक का महत्वपूर्ण एवं पूरक योगदान रहा है। शिक्षक और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रकाश के कारण ही एक सभ्य समाज अस्तित्व में आया और समाज में उत्कृष्टता एवं शालीनता बनी रही। एक शिक्षक अपने ज्ञान, अनुभवों, मूल्यों और उच्च विचारों से हमारे जीवन को सुरक्षी, सरल, श्रेष्ठ, महान और सभ्य बनाता है। प्रत्येक शिक्षक यह प्रयास करता है कि उसका विद्यार्थी जीवन में उच्च पद पर पहुँचे, जीवन भर शालीनता और नैतिकता की बागडोर संभाले और जीवन में सफल हो सके। शिक्षक एक दीपक के समान होता है, जो स्वयं से ही दूसरों को प्रकाश देता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के साथ माता-पिता और एक सच्चे मित्र जैसा रिश्ता भी निभाता है। जब एक शिक्षक से पढ़ा हुआ विद्यार्थी किसी उच्च पद पर पहुँचता है या जीवन में सफलता प्राप्त करता है, तो एक शिक्षक को जो आनंद, प्रसन्नता, शांति, संतोष और सुकून मिलता है, इस स्थिति का वर्णन, अभिलेखन और प्रमाण करना अत्यंत कठिन है। एक शिक्षक कभी भी किसी भी मामले या स्थिति के आधार पर किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं करता है। एक माँ की तरह, सभी छात्र उसके लिए समान हैं। वह सभी को एक आँख से देखता है और सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। एक शिक्षक भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तरह सच्चा, ईमानदार, नेक, सभ्य, विनम्र और नैतिक दिल का होता है। एक शिक्षक का दिल भी बच्चों के दिलों की तरह साफ और शुद्ध होता है। जीवन, समाज, देश और मानवता की प्रगति में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण और मजबूत भूमिका को समझते हुए, हमें और समाज को शिक्षक का दिल से सम्मान करने में संकोच नहीं करना चाहिए। हमने अपने जीवन का स्वर्णिम काल यानी "बचपन" अपने शिक्षकों के साथ बिताया है, उनसे हमने जीवन के सिद्धांत-परीक्षा , शालीनता और सफलता सीखी है और उन्नति हासिल की है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जीवन में और बड़े पदों को प्राप्त करने के बाद भी, हमें अपने शिक्षकों को हमेशा याद रखना चाहिए। घर और परिवार में उनकी तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। जीवन के हर सुख-दुख में और घर-परिवार में हमें अपने शिक्षकों को सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहिए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जब भी याद आए, फ़ोन या पत्र के ज़रिए अपने शिक्षक को याद करें या शिक्षक के घर जाने के लिए समय निकालें। आपको कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि, "अब हमें अपने शिक्षकों से क्या लेना-देना ? उन्हें क्यों बुलाना चाहिए ? उनसे मिलने क्यों जाना चाहिए ?" एक शिक्षक यह आशा करता है और यह उसके लिए बहुत सम्मान की बात है कि उसके छात्र जीवन भर उसका सम्मान करें और उसे याद रखें। जब एक शिक्षक से पढ़ा हुआ छात्र आदर और सम्मान से उसे फ़ोन करता है, उसका हालचाल, सुख-दुख पूछता है, उसे अपने घर बुलाता है या स्वयं अपने परिवार और बच्चों के साथ शिक्षक से मिलने उसके घर जाता है, तो शिक्षक को बहुत ख़ुशी और शांति मिलती है। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति शिक्षक का सम्मान करता है, शिक्षकों की शिक्षाओं और संस्कारों को याद रखता है और जीवन भर उनका पालन करता है, वह जीवन में ज़रूर उन्नति और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेगा और एक शांतिपूर्ण और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं कि जीवन की ऊँचाइयों पर पहुँचने वालों ने अपने शिक्षकों और उनकी दी गई शिक्षाओं को कभी नज़रअंदाज़ नहीं किया और वे जीवन में सफल और सुखी व्यक्ति बनकर उभरे। आज मुझे बड़े दुःख के साथ लिखना पड़ रहा है कि मानवता में जो अनैतिकता, असामाजिकता, असभ्यता, अमानवीयता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, समाज में जो बुराइयाँ दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं और समाज पतन की ओर जा रहा है, उसका मूल कारण अपने गुरुओं को अपने दिलो-दिमाग से भूल जाना, उनका सम्मान न करना और गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षाओं को भूल जाना है। वहीं दूसरी ओर, शिक्षक को भी बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने पद और गरिमा को क्षति पहुँचने और आहत होने से बचाना चाहिए। अंततः, यह करुणा उचित होगा कि हमें जीवन भर अपने गुरुओं का आदर और सम्मान करना चाहिए, समय-समय पर उनसे संपर्क बनाए रखना चाहिए, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए और समय-समय पर गुरुओं के चरणों की वंदना करते रहना चाहिए और उनकी प्रार्थना, आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करते रहना चाहिए।

राज्य पुरस्कार विजेता मास्टर संजीव धर्माणी

बिजली बिभाग ने 3 मिनट में शिकायत नहीं सुनी तो जुर्माना

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : राज्य में बिजली सेवा में जल्द ही सुधार होने वाला है। इस संबंध में ओडिशा विद्युत नियामक आयोग (ओईआरसी) ने एक परिपत्र अधिसूचना जारी की है। इसमें राज्य के लगभग एक करोड़ उपभोक्ताओं से 11 सितंबर तक सूचित राय मांगी गई है। हालाँकि, ओईआरसी द्वारा जारी अधिसूचना में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं यदि उपभोक्ता बिजली सेवा बाधित होने वाले क्षेत्र में कॉल करता है, तो बिजली वितरण कंपनी को 3 मिनट के भीतर जवाब देना होगा। यदि बिजली वितरण कंपनी इस समयावधि में जवाब नहीं देती है, तो जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार, यदि 5 मिनट के भीतर शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, तो बिजली वितरण कंपनी को दंडित किया जाएगा। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 3 दिन के भीतर और शहरी व महानगर निगमों में 3 से 15 दिनों के भीतर नए बिजली कनेक्शन जोड़ने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार, बिजली कटौती और मीटर संबंधी समस्याओं का समाधान भी 3 दिन के भीतर करने को कहा गया है। बिजली वितरण कंपनियों के लिए बनाए गए कार्यनिष्पादन मानक अधिनियम-2004 को 21 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद निरस्त कर दिया गया है और एक नया कार्यनिष्पादन मानक अधिनियम-2025 तैयार किया गया है। हालाँकि, अब टाटा वितरण कंपनियों के लिए मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि वितरण कंपनियां आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करने में विफल रहती हैं, तो वे उपभोक्ताओं को कितनी राशि और कितनी अवधि के भीतर भुगावजा देंगी, इसका भी उल्लेख किया गया है। ओडिशा विद्युत वितरण कंपनियां प्रदर्शन मानक अधिनियम, जो उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली सेवा प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, को आयोग द्वारा अब तक उचित महत्व नहीं दिया गया है। हालांकि इसके संशोधन के लिए पिछली सरकार के दौरान आयोग से बार-बार शिकायत की गई थी, लेकिन आयोग ने नहीं सुना। हालांकि, आयोग ने अब खुद मामला दर्ज करके टाटा वितरण कंपनियों के प्रदर्शन की समीक्षा करने का कार्यक्रम बनाया है। हालांकि, पत्र अधिसूचना मानदंडों में ग्रामीण उपभोक्ता क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों की उपेक्षा को लेकर सवाल उठाए गए हैं। आयोग द्वारा लगाया गया भुआवजा जुर्माना भारत के अन्य आयोगों द्वारा लगाए गए जुर्माने से काफी कम है। आयोग ने मासिक बिल में उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले मानदंडों में यह डेटा शामिल नहीं किया है कि प्रति माह कितने घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती है और यह कितनी बार बाधित होती है।

जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम चौबिस घंटे के अन्दर दुसरी बड़ी लूट

मिर्ची पाउडर आंखों में डाल कर लूट लिये 30 लाख ,इनोवा में आये अपराधी साकेत पर गोली भी दागे

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

जमशेदपुर, चौबीस घंटे के अन्दर अपराधियों ने जमशेदपुर में दूसरी बड़ी घटना को अंजाम दिया है । गुरुवार की दोपहर शहर के बिष्टुपुर गुरुद्वारा इलाके में एक कारोबारी साकेत अग्रवाल से दिनदहाड़े 30 लाख रुपए आंख में लाल मिर्च पाउडर डालकर पुलिस के नाक के नीचे लूट लिए गए। साकेत अग्रवाल यह रकम बैंक में जमा कराने जा रहे थे, तभी यह वारदात हुई। इस दौरान अपराधियों ने गोली भी चलाई ।

बताया गया कि जमशेदपुर में हिन्दुस्तान यूनिलीवर की एजेंसी चलाने वाले साकेत अग्रवाल स्कूटी से बैंक जा रहे थे। बिष्टुपुर गुरुद्वारा से आगे निकले ही थे कि सड़क के किनारे लगी उजले रंग की ईनोवा कार उनके स्कूटी के आगे लगा दिए गए। उसके बाद वहां पहले से तैयार दो बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और अचानक आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया। रुपयों भरा बैग छीनने के बाद इनोवा गाड़ी पर सवार होकर मौके से भाग निकले।

घटना की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी की। पुलिस ने गुरुद्वारा समेत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ।वही घटनास्थल पहुंचे सिटी एसपी कुमार शिवाशीष सहित वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और मामले की पुष्टि की। मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे कारोबारियों और स्थानीय लोगों ने अपराध की बढ़ती घटनाओं पर आक्रोश व्यक्त किया है।

चक्रधरपुर रेल मंडल अन्तर्गत भूवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस के चपेट में हाथी घायल

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

सरायकेला, चक्रधरपुर रेल मंडल के सागरा सोनाखान रेलवे स्टेशन पर किलोमीटर संख्या 453/24 में गुरुवार तड़के 5 बजे भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के चपेट में आने से एक हाथी गंभीर रुप से घायल हो गया है। इस घटना के कारण हावड़ा मुंबई रेल मार्ग में ट्रेनों का परिचालन पूर्ण रुप से ठप हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही राजगांगपुर से वन विभाग की टीम और रेलवे की टीम मौके पर पहुंच कर घायल हाथी को क्रेन की मदद से ट्रैक से हटाने का काम शुरु कर दिया गया है।

बताया जाता कि एक मादा हाथी करीब 15 वर्ष पिछले कुछ दिनों से हाथियों के झुंड से बिछड़ गया था और वह उस ईलाके में अकेले ही घूम रहा था, गुरुवार तड़के सुबह वह रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, इसी दौरान भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया। हाथी के पीछे पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोंटे आयी है, जिससे वह ट्रैक से उठ नहीं पा रहा है। हादसे के बाद भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस को सोनाखान के पहले रोक दिया गया है। वहीं इस घटना के कारण कई ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों में रोक दिया गया है। घटने के बाद ट्रेन नंबर 22358 राजगांगपुर में 5.24 बजे सहित अन्य कई ट्रेनें प्रभावित हुई है। मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है।

5 सितंबर : शिक्षक दिवस पर विशेष- शिक्षा का प्यारा-सा अनुबंध...!

शिक्षक दिवस एवं 'गुरु-शिष्य' संबंध,
शिक्षा के क्षेत्र का प्यारा-सा अनुबंध।
पुरानी पीढ़ी 'यादों की पोटली' खोलें,
नई को नवाचार का पाठ पढ़ने बोले।
यादें गुरुस्थानों व आश्रमों से गुजरती,
जहां पग-पग इन 'रिश्तों' से महकती।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मदिन,
इस दिन की महत्ता गरिमा अनगिन।
कई अर्थों में घर-समाज एवं देशहित,
सरोकारों से वाबस्ता ना होते अहित।
शिक्षक ज्ञान व मार्गदर्शन करें प्रदान,
शिष्य श्रद्धा-समर्पण भाव मिले ज्ञान।

सीखने के भावों से ज्ञान 'ग्रहण' करों,
शिष्य अपने अनुभव को साझा करों।
पुरातन सनातन परंपरा होवे अनवरत,
नैतिक मूल्यों से शिष्य हो रहें समरस।
जीवन के सही 'मार्ग' चलने को प्रेरित,
'शिष्य गुरु प्रति पूर्ण सम्मान उद्वेलित।

संजय एम तराणेकर

चेयरमैन करमजीत सिंह रिंटू और सीनियर डिप्टी मेयर प्रियंका शर्मा द्वारा बाढ़ ग्रस्त गांवो का किया गया निरीक्षण : कहा, सभी तरह की राहत सामग्री पहुंचाएंगे

अमृतसर,4 सितंबर (साहिल बेरी)

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर के चेयरमैन करमजीत सिंह रिंटू और नगर निगम अमृतसर की सीनियर डिप्टी मेयर प्रियंका शर्मा द्वारा अपने साथियों की टीम के साथ अजनाला के बाढ़ ग्रस्त गांव का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा लगभग 9 गांवो में जाकर प्रभावित लोगों से बातचीत की गई और उनकी समस्याएं भी जानी गई। इस अवसर पर करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि पंजाब और पंजाबियों पर बहुत ही बड़ी आफत आई है। इसके बावजूद सभी के हौसले बुलंद है। उन्होंने कहा कि इस बड़ी आफत से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।

करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि गांवो के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जिला प्रशासन द्वारा इस संकट की घड़ी में बाढ़ ग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने, अपनी टीम और अपनी पार्टी की ओर से डटकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार सभी उचित कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि गांवो का निरीक्षण के दौरान जो जो मुश्किलें देखी गई है, उसे पार्टी के सीनियर नेताओं के ध्यान में भी लाया जाएगा ।करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि प्रभावित लोगों को बहुत ही सहूलतो की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम द्वारा इन सहूलतो के लिए सभी तरह की सामग्री कल से प्रभावित लोगों तक पहुंचानी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी टीम द्वारा प्रभावित लोगों को राशन, बिस्तरे, दवाइयां और वित्तीय सहायता भी दी जाएगी ।सीनियर डिप्टी मेयर प्रियंका शर्मा ने कहा कि बाढ़ से बहुत ही बर्बादी हुई है। लोगों के घर गिर गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम अमृतसर की ओर से भारी संख्या में मच्छरों को मारने के लिए फागिंग मशीने दवाइयां सहित जिला प्रशासन को पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वह और उनकी टीम प्रभावित लोगों को हर तरह की सामग्री पहुंचाएगी। इस अवसर पर रितेश शर्मा,विशाखा सिंह अरविंद भट्टी, पार्षद विजय कुमार

,शमशेर सिंह संधू,सुखबीर सिंह सोनी, काजल बॉबी, अरविन भकना, धर्मवीर बॉबी,साहिल सगर, अनेक सिंह, गुरप्रीत सिंह कटारिया, बलविंदर सिंह भी मौजूद थे।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने विधायक श्री धालीवाल द्वारा प्रस्तुत 2 हज़ार करोड़ रुपए के राहत पैकेज संबंधी मांग पत्र पर विचार कर समर्थन का भरोसा दिया

केंद्र सरकार बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र राहत और पुनर्वास के लिए पंजाब को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी – केंद्रीय मंत्री श्री चौहान
केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने हल्का अजनाला के बाढ़ प्रभावित गाँव घोहनेवाला का दौरा कर पीड़ितों का हालचाल जाना

अमृतसर/अजनाला/राजासांसी, (साहिल बेरी)

पिछले 9 दिनों से हल्का अजनाला में रावी दरिया की भीषण बाढ़ से जूझ रहे पीड़ितों का हालचाल लेने और राहत कार्यों का जायज़ा लेने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज चौहान आज विशेष रूप से हल्के के सीमावर्ती गाँव घोहनेवाला पहुँचे। उनके साथ हल्का विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब कुलदीप सिंह धालीवाल, पंजाब सरकार के मंत्रीगण, पूर्व मंत्री, विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता तथा ज़िला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। मौके पर उन्हें पीड़ितों को तत्काल राहत पहुँचाने, जानमाल की सुरक्षा और पुनर्वास कार्यों में पंजाब सरकार, राज्यपाल, सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ, अन्य सरकारी एजेंसियों तथा सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की संतोषजनक भूमिका से अवगत कराया गया।

इस अवसर पर विधायक व पूर्व मंत्री श्री धालीवाल ने केंद्रीय मंत्री से अपील की कि इन बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र राहत और पुनर्वास हेतु केंद्र सरकार से तत्काल सहायता दी जाए। उन्होंने बताया कि हल्का अजनाला भारत-पाक सीमा पर लगभग 49 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित है और इसी सीमा से सटी रावी दरिया की बाढ़ लगभग हर वर्ष यहाँ जानमाल का बड़ा नुकसान पहुँचाती है। सीमावर्ती व ग्रामीण इलाकों के लोग बीएसएफ, पंजाब पुलिस और प्रशासन के सहयोग से नशा व हथियार तस्करी, घुसपैठ जैसी दुश्मन की साज़िशों को नाकाम करते हुए हमेशा देश की एकता और अखंडता की रक्षा में तत्पर रहते हैं। 1965, 1971, 1999 की जंगों और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय भी यहाँ के लोग बीएसएफ के साथ चट्टान बनकर खड़े रहे।

धालीवाल ने श्री चौहान को बताया कि स्वतंत्रता के बाद यहाँ के किसानों और खेत मज़दूरों ने वीरान, जंगलनुमा ज़मीन को कड़ी मेहनत और संघर्ष से उपजाऊ बनाकर देश के अन्न भंडार में लगातार योगदान दिया है।

इससे पहले श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा राजासांसी (अमृतसर) पर विधायक व पूर्व मंत्री श्री धालीवाल और पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने पंजाब सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री श्री चौहान का स्वागत किया और उन्हें हल्का अजनाला के बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास व राहत हेतु पहले चरण में 2 हज़ार करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज और पंजाब सरकार के केंद्र सरकार के पास लंबित 60 हज़ार करोड़ रुपए के फंड को तत्काल जारी कराने की मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा।

धालीवाल ने विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि 1988 की तुलना में इस बार रावी दरिया में आई बाढ़ ने हल्का अजनाला के आर्थिक, सामाजिक, कृषि, पशुधन, छोटे व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पुल-पुलियों और मूलभूत ढांचे को पूरी तरह तबाह कर दिया है तथा कई कीमती जानें भी ले ली हैं। इस नुक़सान की भरपाई के लिए पहले चरण में केंद्र सरकार द्वारा 2 हज़ार करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि लगभग 2 महीने पहले जुलाई के पहले सप्ताह में उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल से मुलाक़ात कर आवश्यक फंड जारी करने की मांग की थी। श्री पाटिल ने शीघ्र फंड जारी करने का भरोसा दिया था, परंतु अब तक यह वादा पूरा नहीं हुआ। धालीवाल ने श्री चौहान से आग्रह किया कि एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते वे इस मुद्दे पर अपने सहयोगी मंत्री श्री पाटिल से विशेष ध्यान दिलवाएँ।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज चौहान ने विधायक श्री धालीवाल द्वारा घोहनेवाला गाँव में प्रस्तुत जमीनी हालात और एयरपोर्ट राजासांसी पर दिए गए मांग पत्र का संज्ञान लेते हुए भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार शीघ्र ही राहत और पुनर्वास हेतु पंजाब सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

विधायक व पूर्व मंत्री श्री कुलदीप सिंह धालीवाल, पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज चौहान को हल्का अजनाला के बाढ़ पीड़ितों हेतु पहले चरण में तत्काल 2 हज़ार करोड़ रुपए वित्तीय पैकेज और पंजाब सरकार के केंद्र सरकार के पास लंबित 60 हज़ार करोड़ रुपए जारी करने संबंधी मांग पत्र सौंपते हुए।

विधायक व पूर्व मंत्री श्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा दिए गए मांग पत्र की विषयवस्तु पर चर्चा करते समय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज चौहान, पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के साथ।

मेयर भाटिया ने किया बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा

अमृतसर, 4 सितंबर (साहिल बेरी)

अमृतसर, – पिछले दिनों आई भयावह बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेयर भाटिया जी राहत सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अजनाला पहुंचे। इस अवसर पर पार्षद वरिंदर विक्की दत्ता, पार्षद सतनाम सिंह, लाटी पहलवान, जसपिंदर सिंह वार्ड इंचार्ज और सहयोगियों के साथ मिलकर गाँव कोट रजादा और बेदी छन्ना में ज़रूरत का सामान उपलब्ध करवाया गया। इसके साथ ही उनकी टीम ने अजनाला से जुड़े बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया।

मेयर भाटिया जी के नेतृत्व में पहुँची टीम ने ग्रामीणों का हालचाल जाना और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द ज़रूरी सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी।

मेयर जी ने लोगों से अपील की कि हम सब मिलकर मानवता पर आई इस आपदा का डटकर सामना करें।

जिन परिवारों के घर बाढ़ के कारण नष्ट हो चुके हैं, उनकी हरसंभव सहायता करने के लिए संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है और मानवता की सेवा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है।

धन-धन बाबा दंदू राम जी बैरागी के पवित्र आशीर्वाद के अंतर्गत, डेरा के महंत श्री बलदेव राज बैरागी जी के नेतृत्व में आज बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया

अमृतसर, 4 सितंबर (साहिल बेरी)

डेरा की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों के लिए तिरपाल और राशन सामग्री से भरे वाहन रवाना किए गए। इस अवसर पर महंत बलदेव राज बैरागी जी ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता करना मानवता का सबसे बड़ा फर्ज है। डेरा हमेशा से ही समाज सेवा को प्राथमिकता देता आया है और कठिन समय में जरूरतमंदों के साथ खड़े रहना डेरा की प्राचीन परंपरा रही है।

उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को छत और भोजन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए तिरपाल और राशन सामग्री बांटने का निर्णय लिया गया है। इस सहायता से परिवारों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। महंत बलदेव राज बैरागी ने सभी सेवादारों का धन्यवाद किया और लोगों से अपील की कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सभी को आगे आना चाहिए।

अमृतसर : सूबा सरकार करेगी हड़ ग्रस्त परिवारों की हर संभव सहायता : संजय सिंह

कैबिनेट मंत्री ई .टी .ओ . और विधायक धालीवाल ने हड़ प्रभावित इलाकों के जरूरतमंदों में बांटी राहत सामग्री
कहा – पंजाब सरकार हर मुश्किल में राज्य के प्रभावित लोगों के साथ

अमृतसर 4 सितंबर (साहिल बेरी)

राज्यसभा सदस्य श्री संजय सिंह, कैबिनेट मंत्री श्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. और विधायक श्री कुलदीप सिंह धालीवाल हड़ प्रभावित क्षेत्र रमदास के नजदीकी गांवों के लोगों के साथ इस संकट की घड़ी में दुख बांटने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांव घोनेवाल व आसपास के गांवों में हड़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की।श्री संजय सिंह ने कहा कि सूबा सरकार हड़ पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करेगी। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा लोगों के हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और पीड़ित परिवारों को राशन, तिरपाल, पशुओं के लिए चारा, चिकित्सीय सुविधा और अन्य आवश्यक सहूलियतें मुहैया करवाई जा रही हैं। हड़ प्रभावित परिवारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि पानी का स्तर कम होते ही तुरंत गिरदावरी का काम शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही लोगों को उनका बनता मुआवजा दिया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का हर नेता, पदाधिकारी और वालंटियर लगातार राहत सामग्री पहुंचाकर पीड़ितों की मदद कर रहा है।उन्होंने आगे बताया कि पंजाब सरकार हड़ प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य कर रही है, जिसमें पूरे पंजाब के लोग सहयोग कर रहे हैं। इस आपदा की घड़ी में सभी पंजाबियों को एकजुट होकर इन जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार हर मुश्किल में राज्य के प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है।इस मौके कैबिनेट मंत्री श्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि हड़ की वजह से अजनाला क्षेत्र के लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, यहां तक कि उनके बिस्तर और कपड़े तक नहीं बचे। उन्होंने बताया कि वे आज पीड़ित परिवारों के लिए राशन और पशुओं के लिए हरा चारा लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर व्यक्ति को उसका बनता मुआवजा अवश्य दिया जाएगा।

इस अवसर पर हलका विधायक श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि हम लोगों के साथ खड़े हैं और मैं रोजाना हर गांव में जाकर लोगों को राशन उपलब्ध करवा रहा हूं। उन्होंने बताया कि पूरा जिला प्रशासन हड़ प्रभावित परिवारों के लिए दिन-रात काम कर रहा है। श्री धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में फसलों के नुकसान का मुआवजा देने के लिए गिरदावरी के आदेश जारी किए गए हैं और लोगों को पंजाब सरकार की ओर से अधिकतम मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार हर मुश्किल में राज्य के प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है।

उन्होंने अपील की कि इस समय सभी को पार्टीबाजी से ऊपर उठकर एकजुट होकर जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। यह समय राजनीति करने का नहीं बल्कि इंसानियत निभाने का है। जब लोग मुश्किल में हैं तो हमारा फर्ज है कि उनके साथ खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाएं।इस मौके पर विधायक डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर, श्री मुखविंदर सिंह विरदी, जिला प्रधान श्री प्रभावीर सिंह बराड़, हलका इंचार्ज लोकसभा श्री जसकरण बंदेशा, ग्रामीण जिला प्रधान गुरप्रताप सिंह संधू, करणबीर सिंह टिवाणा, सरबजोत सिंह धंजल, गीता गिल समेत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे।

जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार – उपभोक्ताओं को राहत से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी- व्यापार मंडल

अमृतसर 4 सितम्बर (साहिल बेरी)

पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्यारे लाल सेठ और महासचिव समीर जैन, जनरल सेक्रेटरी यूनिट अमृतसर बलबीर भसीन ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों और कर दरों में पुनर्गठन को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताते हुए व्यापार मंडल की लंबे समय से चल रही मांग पर सरकार द्वारा किए फ़ैसले का स्वागत किया । केंद्र का आभार व्यक्त किया है। व्यापार मंडल ने कहा कि इन सुधारों से छोटे व्यापारियों, उपभोक्ताओं और देश की अर्थव्यवस्था – तीनों को बड़ा लाभ होगा ।

व्यापार मंडल ने कहा कि 400 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स घटाने से आम नागरिकों को रोज़मर्रा के खर्चों में सीधी राहत मिलेगी और उपभोग में भारी वृद्धि होगी। यही बढ़ता उपभोग खुदरा व्यापार और छोटे दुकानदारों को नई ताक़त देगा।

प्रदेश व्यापार मंडल ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की हालिया रिपोर्ट भी यही संकेत देती है कि जीएसटी सुधारों के चलते आगामी त्योहार सीजन में खपत में 7–8% की वृद्धि होगी। इससे रिटेल ट्रेड, छोटे दुकानदारों और थोक व्यापारियों को सीधा लाभ होगा।

व्यापार मंडल ने बीमा सेवाओं को जीएसटी से मुक्त करने के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि इससे मध्यमवर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम अब पहले से सस्ते होंगे। महामारी के बाद और बढ़ती स्वास्थ्य लागत के बीच यह कदम आम परिवारों के लिए बेहद सहायक सिद्ध होगा और बीमा कवरेज को बढ़ावा देगा।

व्यापार मंडल ने कहा कि इन सुधारों से बहुआयामी लाभ होंगे –

- उपभोक्ताओं के पास अधिक क्रय शक्ति होगी, जिससे बाज़ार की मांग बढ़ेगी।
- उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियाँ तेज़ होंगी, नए रोज़गार पैदा होंगे।
- टैक्स दरों के सरलीकरण से जीएसटी अनुपालन आसान और कम खर्चीला होगा।
- केवल दो मुख्य कर स्लैब रहने से राजस्व संग्रह बेहतर होगा और व्यापारिक माहौल में स्थिरता आएगी।

प्यारे लाल सेठ और समीर जैन ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार इन सुधारों का भारत की जीडीपी पर भी सीधा असर पड़ेगा और अगले वित्त वर्ष में 0.5% से 0.7% तक अतिरिक्त वृद्धि संभव है। इससे सरकार की आय बढ़ेगी और भारत की स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था में और अधिक मज़बूत होगी।

व्यापार मंडल ने कहा कि यह सुधार केवल कर ढांचे में बदलाव नहीं हैं, बल्कि भारतीय व्यापार के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय हैं। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आने वाले समय में हर छोटे व्यापारी से लेकर देश की समग्र अर्थव्यवस्था तक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

समाजिक सेवा और युवाओं के सशक्तिकरण की प्रेरणा का स्रोत – पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती लक्ष्मीकांता चावला का अमृतसर ग्रुप एन.सी.सी. दौरा

अमृतसर, 4 सितम्बर (साहिल बेरी)

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती लक्ष्मीकांता चावला ने अमृतसर ग्रुप एन.सी.सी. का दौरा किया। इस अवसर पर ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर के.एस. बावा ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि अमृतसर ग्रुप एन.सी.सी. के लिए यह गर्व की बात है कि श्रीमती चावला उनके बीच आईं। उन्होंने बताया कि श्रीमती चावला ने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ सामाजिक सेवा को समर्पित किया है।

ब्रिगेडियर बावा ने कहा कि श्रीमती चावला अपनी युवावस्था से ही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ निर्भीक योद्धा और वंचित वर्गों की सशक्त आवाज़ रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनका योगदान अविस्मरणीय है, जब उन्होंने अस्पतालों, जनस्वास्थ्य ढांचे और बीमारियों से बचाव हेतु जनजागरूकता अभियानों को सुदृढ़ करने में सराहनीय कार्य किया।

अपने दौरे के दौरान श्रीमती चावला ने ब्रिगेडियर के.एस. बावा, ग्रुप कमांडर और एन.सी.सी. स्टाफ़ से भेंट की और स्वस्थ, संवेदनशील एवं जिम्मेदार समाज के निर्माण में एन.सी.सी. की भूमिका की प्रशंसा की। उन्हें सरहदी जिलों में एन.सी.सी. की गतिविधियों की जानकारी दी गई, जहां कैडेट्स अनुशासन, देशभक्ति और आपदा राहत संबंधी जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सेवा और युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए एन.सी.सी. की प्रतिबद्धता की सराहना की।

यह दौरा पूरी टीम के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ और नई ऊर्जा का संचार किया। कार्यक्रम का समापन ग्रुप कमांडर द्वारा सम्मानित अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करने से हुआ, जिसके माध्यम से उनकी निस्वार्थ सेवा, महिला सशक्तिकरण और मजबूत समाज निर्माण की दिशा में योगदान को नमन किया गया। श्रीमती चावला का यह दौरा प्रेरणा की अमिट छाप छोड़ गया और पूरी टीम को निस्वार्थ सेवा के इस पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नया जोश प्रदान किया।

मौसम साफ होते ही गिर्दावरी का काम किया जाएगा शुरू – डिप्टी कमिश्नर

धुसी में पड़े कटाव को भरने की भी हो रही है तैयारी
साँप के काटने की स्थिति में तुरंत बाढ़ राहत केंद्र पर पहुँचकर लगवाएँ डॉक्टरों से टीका

अजनाला, (साहिल बेरी)

लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की ज़िम्मेदारी निभा रही अमृतसर की डिप्टी कमिश्नर श्रीमती साक्षी साहनी ने गाँव घोनेवाल में प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जैसे ही बाढ़ का पानी घटेगा और मौसम साफ होगा, विशेष गिर्दावरी का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में साफ मौसम की संभावना है और यदि मौसम अनुकूल रहा तो हमारे पटवारी प्रत्येक प्रभावित घर में पहुँचकर हुए नुक़सान का जायज़ा लेंगे। यह रिपोर्ट सरकार को भेजने के बाद जल्द से जल्द मुआवज़े की राशि बाँटने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका, यानी घोनेवाल (जहाँ धुसी बाँध टूटा था और सबसे अधिक नुक़सान हुआ) से गिर्दावरी का काम शुरू किया जाए।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस समय हमारी टीमें, गैर-सरकारी संगठन, रेड क्रॉस अमृतसर, विभिन्न संस्थाएँ, कार सेवा वाले महापुरुष, नौजवान सेवा सोसायटियाँ और अन्य वॉलंटियर पंजाब भर से पहुँचकर ज़रूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं।

वधिक डिप्टी कमिश्नर श्री रोहित गुप्ता ने बताया कि अमृतसर ज़िले के 190 गाँव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें लगभग 1.35 लाख की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण अमृतसर ज़िले में पाँच कीमती मानव जीवन खोए गए हैं और 91 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं।

पशुधन के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 12 पशुओं की मौत और कई के लापता होने की सूचना है। उन्होंने कहा कि हमारी टीमों ने बचाव कार्यों में भाग लेते हुए पानी से पूरी तरह घिरे 2734 व्यक्तियों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। वर्तमान में लोगों की सुविधा के लिए 16 स्थानों पर बाढ़ राहत केंद्र चल रहे हैं, जहाँ ज़रूरतमंद लोगों के रहने और पशुओं को रखने की व्यवस्था है। इसके अलावा, इन केंद्रों से ही लोगों को राशन और पशुओं के लिए चारा व फ़ीड वितरित की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इन कैंपों में हमारी डॉक्टर टीम 24 घंटे मौजूद रहकर ज़रूरतमंदों का इलाज कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बाढ़ के पानी में साँपों के काटने की घटनाएँ अधिक हो रही हैं, इसे हल्के में न लें। यदि किसी को साँप काट ले तो तुरंत इन राहत केंद्रों में पहुँचे, जहाँ डॉक्टरों के पास एंटी-वेनम टीका उपलब्ध है, और वही सबसे सुरक्षित उपचार है। उन्होंने कहा कि लोग घरेलू उपायों पर भरोसा कर अपनी जान जोखिम में न डालें और तुरंत डॉक्टरों की मदद लें।

सरहद पार से चल रहे तस्करी रैकेट का पर्दाफाश; 2.02 किलो हेरोइन, 3.5 लाख रुपये की ड्रग मनी और 4 पिस्तौल बरामद, तीन गिरफ्तार

पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय था गैंग : डीजीपी गौरव यादव
हवाला के जरिए पाकिस्तान भेजी जानी थी बरामद की गई ड्रग मनी : सीपी अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर

अमृतसर, 4 सितम्बर (साहिल बेरी)

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सरहद पार से जुड़े संगठित हथियार और हवाला नेटवर्क में शामिल तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने गुरुवार को दी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमृतसर के गांव कोट महिताब निवासी हरप्रीत सिंह (२३), तरनतारन के गांव सुरसिंह निवासी गुरपाल सिंह (२१) और तरनतारन के गांव वायरिंग निवासी रणजोध सिंह (३३) के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से २.०२ किलो हेरोइन, चार पिस्तौल (एक ग्लॉक और तीन .30 बोर पिस्तौल), ३.5 लाख रुपये हवाला मनी और एक मोटरसाइकिल बरामद की है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि यह गिरोह पाकिस्तान से हेरोइन और हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता था और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय था। शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी हरप्रीत और गुरपाल, जो पहले मलेशिया गए थे, सीमा पार के तस्करों के संपर्क में थे।

उन्होंने कहा कि थाना गेट हकीमा में मामला दर्ज किया गया है और गिरोह के अन्य नेटवर्क और कड़ियों को उजागर करने के लिए आगे की जांच जारी है। पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि हरप्रीत और गुरपाल को पहले २१० ग्राम हेरोइन और मोटरसाइकिल सहित पकड़ा गया था। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने एक निर्धारित स्थान से 1.8 किलो हेरोइन और दो .30 बोर पिस्तौल और बरामद किए। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि हरप्रीत २०२३ में सात महीने के लिए मलेशिया गया था जबकि गुरपाल २०२१ में मलेशिया गया और २०२३ में लौटा। मलेशिया में दोनों एक-दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन पाकिस्तान आधारित एक तस्कर के संपर्क में थे और उसी के निर्देशों पर उन्हें नशे और हथियारों की खेपें मिलती थीं। सीपी ने बताया कि गुरपाल सिंह के खुलासे पर तीसरे आरोपी रणजोध को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से दो पिस्तौल और 3.5 लाख रुपये ड्रग मनी बरामद हुई। यह रकम तस्करी के धंधे से जुड़ी हुई थी जिसे हवाला के जरिए पाकिस्तान भेजा जाना था। इस संबंध में थाना गेट हकीमा, अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धारा २१C, १७A, २७B और २९ तथा आर्म्स एक्ट की धारा २५ के तहत एफआईआर नंबर ३३५ दिनांक ३०.०८.२०२५ दर्ज की गई है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023